सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 254, नई दिल्ली । रविवार, 24 नवम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

यह मत मानिए कि जीत ही सब कुछ है, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीतना चाहते हैं...

03 दिल्ली की सफ़ाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा– मेयर

06 ऋतुओं को निगलने लगा प्रदूषण

08 महाराष्ट्र और यूपी चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर जताई खुशी

दिल्ली के वाहन चालक ध्यान दें! परिवहन विभाग ने गाड़ियों के लिए रंग-कोडित ईंधन स्टीकर अनिवार्य किया

दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहनों के लिए रंग-कोडित ईंधन स्टीकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम बढ़ते प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए उठाया गया है। स्टिकर वाहन के ईंधन के प्रकार को पहचानने में मदद करेंगे। यह नियम एक अप्रैल 2019 से प्रभावी नए वाहनों और 31 मार्च 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों दोनों पर लागू होता है।

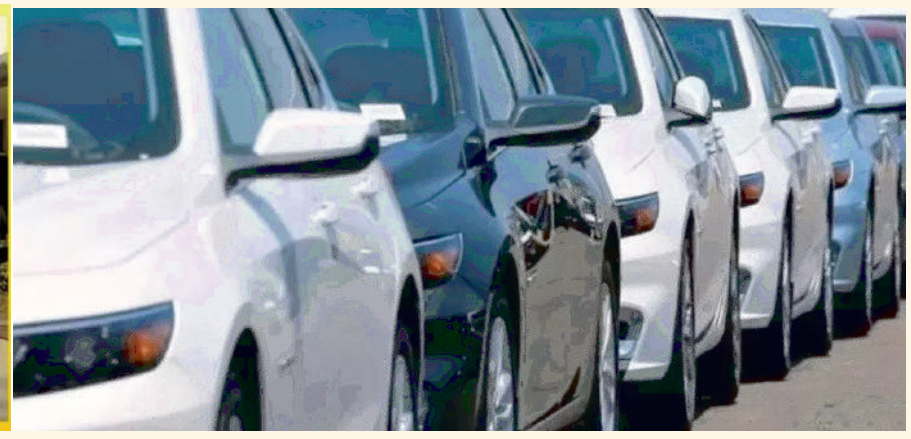

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहन मालिकों को बढ़ते प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए ईंधन के प्रकारों की पहचान करने में मदद करने के लिए अपने वाहनों पर रंग-कोडित स्टीकर लगाना अनिवार्य किया है। विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार यह निर्देश 12 अगस्त, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 में बाद के संशोधनों के अनुरूप है।

नोटिस में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में वाहन मालिकों को अब क्रोमियम-आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। रंग-कोडित स्टिकर जांच के दौरान वाहन के ईंधन के प्रकार को पहचानने में प्रवर्तन कर्मियों की सहायता के लिए डिजाइन किए गए हैं।

2019 से पंजीकृत पुराने और नए दोनों वाहनों पर लागू

विभाग के अनुसार यह यह नियम एक अप्रैल, 2019 से प्रभावी नए वाहनों और 31 मार्च, 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों दोनों पर लागू होता है। वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए उनके विंडस्क्रीन पर स्टीकर चिपका हुआ है। पुराने वाहनों के मालिकों को स्टिकर लगाने के लिए अपने संबंधित वाहन डीलरों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा

इसके अलावा सोसाइटी आफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) की वेबसाइट या परिवहन विभाग के पोर्टल के माध्यम से ईंधन-आधारित रंग-कोडित स्टीकर के साथ-साथ हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) को अपने घर पर लगवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है।

जिन वाहनों पर एचएसआरपी और स्टीकर नहीं होगा उन वाहनों का चालान किया जाएगा। स्टीकर में पंजीकरण संख्या, पंजीकरण प्राधिकरण, एक लेजर-ब्रांडेड पिन और वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर जैसे विवरण होते हैं।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! धड़ाधड़ कट रहे चालान...

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली यातायात पुलिस ने इस साल 31 अक्टूबर तक राष्ट्रीय राजधानी के 14 प्रमुख बाजारों में अनुचित पार्किंग के लिए 49 हजार से अधिक चालान जारी किए हैं, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 26.2 प्रतिशत अधिक है। इन बाजारों में करोल बाग, सदर बाजार, चांदनी चौक, कमला नगर, गांधी नगर, विकास मार्ग, सरोजिनी नगर, ग्रीन पार्क, लाजपत नगर, यूसुफ सराय, महिपालपुर, राजौरी गार्डन, तिलक नगर और सेक्टर-10 द्वारका शामिल हैं।

यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, यातायात पुलिस ने बीते वर्ष 31 अक्टूबर तक 39,100 चालान जारी किए थे, जो इस वर्ष बढ़कर 49,348 हो गए हैं। अधिकारी ने बताया कि इन 14 बाजारों में रोजाना काफी भीड़ रहती है। आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यातायात विभाग द्वारा इन व्यस्त व्यावसायिक केंद्रों में पार्किंग उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की गई है।

अनुचित पार्किंग पर है 500 रुपये का जुर्माना

राष्ट्रीय राजधानी में अनुचित पार्किंग के लिए जुर्माना 500 रुपये है। इसके अलावा, पुलिस ने इस साल 31 अक्टूबर तक इन स्थानों से 28,935 वाहनों को जब्त किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 22,928 वाहनों को जब्त किया गया था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस साल 22 अक्टूबर तक शहर के चार प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अनुचित पार्किंग के लिए 39 हजार से अधिक वाहनों पर मुकदमा चलाया गया है। सबसे अधिक 14,949 चालान पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास जारी किए गए, इसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (13,122), हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन (8,089) और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन (3,527) चालान किए गए।

757 वाहन किए गए जब्त

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आटो-रिक्शा के 5,526 चालान, बसों के 1,070 चालान, टैक्सियों के 1,145 चालान, ई-रिक्शा के 3,596 चालान और अन्य वाहनों के 3,612 चालान काटे गए। पुलिस ने इन रेलवे स्टेशनों से 1,460 वाहनों को भी जब्त किया, जिनमें सबसे अधिक 757 वाहन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब्त किए गए।

दिल्ली में सुबह सांसों पर रही आफत, दिन में स्मॉग से राहत; यह इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। शनिवार को दिल्ली का औसत एयर इंडेक्स 412 रहा जो देश में सबसे अधिक है। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि दिन में हवा की दिशा में बदलाव और हल्की हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी आई है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राजधानी में शनिवार सुबह स्मॉग, मध्यम स्तर के कोहर व हवा की गति बेहद कम होने प्रदूषण का स्तर अधिक रहा। इससे हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। इससे सांसों पर आफत जैसी स्थिति महसूस की गई, लेकिन दिन में 11:30 बजे के बाद हवा के दिशा में हुए बदलाव और उत्तर पूर्व की तरफ से हल्की हवा चलने से स्मॉग छठा।

साथ ही गुनगुनी धूप भी खिली। इससे दोपहर में प्रदूषण से काफी हद तक राहत महसूस की गई और एयर इंडेक्स में कमी आई। फिर भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली में दो दिन की राहत के बाद हवा की गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर श्रेणी में बताई। इससे एयर इंडेक्स 400 से अधिक रहा।

कितना रहा दिल्ली का एक्यूआई

सीपीसीबी के अनुसार, शनिवार को दिल्ली का औसत एयर इंडेक्स 412 रहा। इससे शनिवार को दिल्ली देश में सबसे अधिक प्रदूषित रही। इसके बाद बिहार का कटिहार दूसरे स्थान पर रहा, जहां एयर इंडेक्स 355 रहा। सीपीसीबी के अनुसार, नौ बजे दिल्ली का एयर इंडेक्स 422 पहुंच गया था।

उस दौरान दिल्ली में आनंद विहार सहित नौ जगहों पर एयर इंडेक्स 450 से अधिक पहुंच गया था। वहीं, स्विस कंपनी के ऐप आईक्यूएयर (IQair) ने सुबह नौ बजे दिल्ली का एयर इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में 493 बताया।

आईक्यूएयर ऐप के अनुसार, दिन में 11:30 बजे तक एयर इंडेक्स 400 से अधिक बना रहा। दोपहर में एयर इंडेक्स में सुधार हुआ और शाम साढ़े चार बजे तक एयर इंडेक्स 200 से कम 182 बताया। आईक्यूएयर ऐप के अनुसार लेकिन रात आठ बजे एयर इंडेक्स 339 हो गया। वहीं, सीपीसीबी के अनुसार रात आठ बजे दिल्ली का एयर इंडेक्स घटकर 398 हो गया।

अब तक आठ दिन गंभीर श्रेणी में रही हवा की गुणवत्ता

सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में इस माह अब तक आठ दिन एयर इंडेक्स 400 से अधिक गंभीर श्रेणी में रहा है। जिसमें से 16 से 20 नवंबर तक लगातार पांच दिन एयर इंडेक्स 400 से अधिक था। इस वजह से इस बार प्रदूषण अधिक रहा है। दिल्ली में अगले तीन दिन हवा की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रहने की संभावना है।

दिल्ली के प्रदूषण में 16.42 प्रतिशत रही हवा की गुणवत्ता

सीपीसीबी के अनुसार, शनिवार को एनसीआर में गुरुग्राम व फरीदाबाद को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। गुरुग्राम व फरीदाबाद में एयर इंडेक्स 300 से कम खराब श्रेणी में रहा। आइआइटीएम पुणे के डिसिजन सपोर्ट डीएसएस (डीएसएस) के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों के उत्सर्जन की भूमिका 16.42 प्रतिशत रही।

प्रदूषण के धुएं की भूमिका भी अभी 17-18 प्रतिशत के बीच बनी हुई है। वहीं औद्योगिक ईकाइयों से निकलने वाले धुएं की भूमिका 3.12 प्रतिशत रही। वातावरण में पीएम-10 का अधिकतम स्तर 354 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर व पीएम-2.5 का अधिकतम स्तर 216.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा जो स्वीकृत मानक से साढ़े तीन प्रतिशत ज्यादा है।

एनसीआर में शनिवार को सीपीसीबी व आईक्यूएयर ऐप द्वारा प्रदर्शित एयर क्वालिटी इंडेक्स

शहर	सीबीसीबी	आईक्यूएयर
दिल्ली	412	182
गाजियाबाद	339	163
नोएडा	322	163
ग्रेटर नोएडा	307	178
गुरुग्राम	265	150
फरीदाबाद	285	165

नोटः आईक्यूएयर ऐप के एयर इंडेक्स का आंकड़ा शाम साढ़े चार बजे का है।

सीपीसीबी के डाटा के अनुसार शाम चार बजे दिल्ली के इन इलाकों में अधिक रहा एयर इंडेक्स

वजीरपुर- 450
जहांगीरपुरी- 439
विवेक विहार- 438
बवाना- 338
आनंद विहार- 437

ग्रेप-4 के लागू होने से रुका विकास कार्य, अब दिसंबर में शुरू होगा पंजाबी बाग फ्लाईओवर

दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण लागू ग्रेप-4 के चलते पंजाबी बाग फ्लाईओवर का निर्माण कार्य रुक गया है। फ्लाईओवर का 95% काम पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ फिनिशिंग का काम बाकी है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि दिसंबर में फ्लाईओवर चालू हो जाएगा। इस फ्लाईओवर के बनने से वेस्ट दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी।

दिल्ली। दिल्ली में ग्रेप-4 लागू होने के कारण पंजाबी फ्लाईओवर से अभी वाहन चालकों को गुजरने के लिए एक महीना और ठहरना होगा, क्योंकि अभी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य रुका हुआ है। पंजाबी फ्लाईओवर का 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। फ्लाईओवर पर बिजली के खंभे और लाइटें लग चुकी हैं। सड़क के बीचों-बीच बने डिवाइडर पर आधी से अधिक पेंटिंग का कार्य हो गया है।

फ्लाईओवर के पिलर पर भी रंगबिरंगी पेंटिंग बना दी गई है, जो कि लोगों को अपनी आकर्षित कर रही है। यही नहीं फ्लाईओवर के सड़क की तरफ लगे टाइल पर भी नीले रंग का कलर हो गया है। बैरिंग, लाइट कनेक्शन सहित कुछ फिनिशिंग के कार्य ही शेष रह गए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर के महीने में फ्लाईओवर वाहन चालकों के लिए शुरू हो जाएगा। नए साल से पहले लोगों को यह तोहफा मिलेगा।

वेस्ट दिल्ली इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलपमेंट के तहत निर्माण

पंजाबी बाग क्लब रोड स्थित छह लेन वाले फ्लाईओवर को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा वेस्ट दिल्ली इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलपमेंट के तहत निर्माण किया जा रहा है। फ्लाईओवर पर दोनों तरफ से छह कारें आराम से गुजर सकती हैं। फ्लाईओवर की एक तरफ की चौड़ाई 11.50 मीटर है, जबकि दोनों तरफ की चौड़ाई 23 मीटर है। इसके अलावा फ्लाईओवर की लंबाई 1.1 किलोमीटर की है। 308 करोड़ रुपये की लागत से इस फ्लाईओवर को तैयार किया जा रहा है।

फ्लाईओवर के उद्घाटन की तारीख अभी तय नहीं

पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि ग्रेप 4 लागू होने के कारण निर्माण कार्य पर 10-15 दिन का फर्क रहेगा। प्रदूषण के कारण अभी बैरिंग लगना, फिनिशिंग होना जैसे जो कार्य रह गए हैं। यह कार्य नियम हटने के बाद ही हो पाएंगे। धूल-मिट्टी उड़ने वाले सभी कार्यों पर रोक लगा दी गई है। जनरेटर चलेगा नहीं, जैमर चलेगा नहीं तो इस वजह से काम में देरी हो रही है। बिना धूल मिट्टी वाले कार्य ही किए जा रहे हैं। प्रयास जारी है कि दिसंबर के महीने में लोगों के लिए इसे शुरू कर दिया जाए। हालांकि फ्लाईओवर के उद्घाटन की तारीख अभी तय नहीं की गई है।

फ्लाईओवर के पिलरों की पेंटिंग लोगों को लुभा रही

फ्लाईओवर के नीचे करीबन 20 अधिक से पिलर बनाए गए हैं जिन पर पेड़ की बेहतरीन डिजाइन बनाई गई है। साथ ही इन पर पीला रंग किया गया है। जबकि पेड़ को भूरे रंग से बनाया गया है। यह डिजाइन वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को लुभा रही है, जिसकी वजह से लोग वीडियो भी बनाकर ले जा रहे हैं।

फ्लाईओवर के यह हो चुके हैं कार्य

1.1 किलोमीटर के फ्लाईओवर के दोनों तरफ की सड़क का निर्माण कार्य हो चुका है। फ्लाईओवर पर चढ़ते और उतरते समय दोनों तरफ की सड़कें भी बनकर तैयार हैं। फ्लाईओवर पर दोनों तरफ बिजली के खंभे और लाइटें लगाने का कार्य भी आधे से अधिक पूरा हो चुका है। फ्लाईओवर के किनारे रेलिंग लग चुकी है। डिवाइडर पर आधी से अधिक जगह पर पेंटिंग हो चुकी है।

पेड़ों की वजह से एक तरफ रखी गई दो लेन

पंजाबी बाग और मोतीनगर से आने वाले वाहन फ्लाईओवर पर जब चढ़ेंगे तो वहां पर केवल दो कारें ही एक साथ ऊपर चढ़ पाएंगी, क्योंकि यहां पर सड़क के किनारे काफी संख्या में पेड़ लगे हैं, जिसकी वजह से निर्माण कार्य में बांधा आ रही थी। वन विभाग को शिकायत करने के बाद भी जब पेड़ नहीं हटाए गए तो विभाग द्वारा तीन की जगह पर दो लेन बनाकर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया गया है। यही उतरते समय दूसरी तरफ तीन लेन बनी हुई हैं।

सुपरफूड से कम नहीं है डायबिटीज के मरीजों के लिए ये 5 हेल्दी चीजें

जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उन लोगों को अपने आहार में इन चीजों का सेवन से जरुर करना चाहिए। मधुमेह से जूझ रहे लोगों के लिए 5 स्वस्थ स्नैकिंग ऑप्शन है। आइए जानते हैं इन हेल्दी चीजों के बारे में-

भारत में सबसे ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित है। यह स्वास्थ्य समस्या तब उत्पन्न होती है जब शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है या फिर यह ठीक से प्रयोग नहीं करता है। ब्लड शुगर बढ़ने से शरीर में ये लक्षण देखने को मिलते है। जैसे कि- ह्रदय रोग, दृष्टि हानि, गुर्दे की बीमारिया, तंत्रिका क्षति पहुंचती है, त्वचा की समस्याओं और प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्याओं जैसे प्रमुख बीमारियों को जन्म देती है। आइए जानते हैं डायबिटीज के मरीजों के लिए कौन-सी हेल्दी चीजें है।

मखाना (फॉक्स नट्स)

डायबिटीज के मरीजों के लिए मखाना का सेवन बेहद फायदेमंद होता है। इसे फॉक्स नट्स के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर हर घर में मखाने को घी और मसालों के साथ भूना जाता है। यह एक सर्वश्रेष्ठ स्नैकिंग ऑप्शन है। इसमें उच्च पोषण मौजूद होता है और कम कैलोरी होती है। इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो यह ब्लड शुगर के लेवल को मैनेज करता है।

भुना हुआ चना

भुने हुए चना का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही यह रक्तप्रवाह में ग्लूकोज को धीरे-धीरे कम करने में मदद करता है। आपको प्रतिदिन चना सेवन जरुर करना चाहिए।

उबले अंडे

अंडे का सेवन करने से कई न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं और साथ ही में कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आपर उबले अंडे का सेवन करते हैं, तो आपको 6.3 ग्राम प्रोटीन और आधा ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके सेवन से आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं।

ड्राई **फ्रूट्स** का सेवन करें

बादाम, अखरोट और काजू जैसे सूखे मेवे डायबिटीज रोगियो के लिए स्वस्थ आहार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आप इसका सेवन सीमित में ही करें। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आप कितना ड्राई फ्रूट का सेवन करें।

ढोकला

गुजरात का सबसे फेमस ढोकला खाने से डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। ढोकला में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल मे रहता है और यह पाचन के लिए सबसे बढ़िया होता है।

बदलते मौसम में रूखी और बेजान हो जाती है आपकी त्वचा, तो अपनाएं ये स्किन केयर रुटीन

बदलते मौसम में तापमान में भी बदलाव होता है, जिसके कारण त्वता के ड्राई होने की समस्या पैदा हो जाती है। स्किन की चमक बनी रहे और ड्राई स्किन की समस्या से बचने के लिए हम इस आर्टिकल के जरिए आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं।

बदलते मौसम में त्वचा की अच्छे से देखभाल करने की जरूरत होती है। क्योंकि जब आप स्किन की अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, तो स्किन संबंधी कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसमें स्किन का ड्राई होना भी शामिल है। बदलते मौसम में तापमान में भी बदलाव होता है, जिसके कारण त्वता के ड्राई होने की समस्या पैदा हो जाती है। इससे स्किन की चमक भी कम हो जाती है। स्किन की चमक बनी रहे और ड्राई स्किन की समस्या से बचने के लिए हम इस आर्टिकल के जरिए आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। आप इन टिप्स को अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकती हैं।

ठंडे और गर्म पानी का इस्तेमाल न करें

बदलते मौसम में पानी की वजह से भी स्किन ड्राई हो सकती है। क्योंकि बदलते मौसम में लोग ठंडे और गर्म दोनों तरह के पानी का यूज करते हैं। ऐसा करने से त्वचा ड्राई हो सकती है और इससे स्किन का नेचुरलऑइल कम हो जाता है। वहीं ऐसी समस्या न हो, इसके लिए आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और फिर फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करें।

सनस्क्रीन का इस्तेमाल

बता दें कि बदलते मौसम में ड्राई स्किन से बचने के लिए आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल सिर्फ गर्मियों में ही किया जा सकता है। जबकि ऐसा नहीं है। सर्दियों और गर्मियों दोनों में सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकती हैं। बाहर जाने के दौरान सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, वहीं आप हर 4 घंटे में सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि सनस्क्रीन अप्लाई करने से पहले मॉइस्चराइजर करना न भूलें।

इन बातों का भी रखें खास ध्यान

फेस को अच्छे से साफ करें और इस दौरान गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।

वहीं फेस वॉश करने के बाद चेहरे को अच्छे से मॉइश्चराइज करें।

बेंगलुरु के इस फेमस मंदिर में शांत स्वरूप में हैं मां काली, आप भी कर आएं दर्शन

मां काली को समर्पित मंदिरों में काली मां की प्रतिमा या तस्वीरें क्रोध वाली देखी होंगी। अक्सर मां काली अपनी जीभ निकाले गुस्से से देख रही हैं। लेकिन बता दें कि बेंगलुरु के इस मंदिर में मां काली का शांत स्वरूप देखने को मिलेगा।

बेंगलुरू में कई ऐसे मंदिर हैं, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा फेमस और खास माने जाते हैं। बेंगलुरू को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। इस शहर में बहुत सारी इमारतें और पार्क हैं। बेंगलुरू की ऐतिहासिक जगहें देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी फेमस हैं। बेंगलुरु में एक ऐसा मंदिर है, जो मां काली को समर्पित है। वैसे तो आपने मां काली को समर्पित तमाम मंदिर देखे होंगे, लेकिन बेंगलुरू का यह मंदिर सबसे खास है।

मां काली को समर्पित मंदिरों में काली मां की प्रतिमा या तस्वीरें क्रोध वाली देखी होंगी। अक्सर मां काली अपनी जीभ निकाले गुस्से से देख रही हैं। लेकिन बता दें कि बेंगलुरु के इस मंदिर में मां काली का शांत स्वरूप देखने को मिलेगा। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बेंगलुरु के मां काली को समर्पित इस खास मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं।

मां काली का अनोखा मंदिर

मां काली को समर्पित इस मंदिर में मां सौम्य रूप में विराजमान हैं। यह मंदिर गविपुरम गुट्टाहल्ली में केम्पमबुधि झील के किनारे एक पहाड़ी पर है। मां काली के दर्शन के लिए पहाड़ी पर चढ़ाई करनी पड़ती है। वहीं इस मंदिर में मां काली का रूप एक चट्टान पर दिखेगा। क्योंकि चट्टान पर देवी काली के स्वरूप को उकेरा गया है। देखने से आपको लगेगा कि यहां पर मां काली की मूर्ति चट्टान काटकर बनाई गई है। इस मूर्ति को करीब 3 फीट ऊंचा बनाया गया है। इस मंदिर में मां काली मुस्कुराते हुए शांत रूप में नजर आती हैं। यह भारत के फेमस मंदिरों में से एक है।

कैसे पहुंचे मंदिर

बता दें कि इस मंदिर में भले ही मां काली शांत रूप में हैं, लेकिन यहां पर मंत्र, वशीकरण, जादू और नजर दोष का इलाज होता है। माना जाता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन लोग अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए खास तौर पर पूजा करवाते हैं।अमावस्या के अलावा शुक्रवार और मंगलवार के दिन मंदिर में आना शुभ माना जाता है। वहीं अभिषेक जल प्राप्त करने के लिए मंदिर के अंदर रहने का समय सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक है।

बस से- आप केन्गेरी बस टर्मिनल से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां से मंदिर पहुंचने में आपको करीब 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है।

समय- सुबह 06:30 से शाम 08:30 मिनट तक।

यह बेंगलुरू के फेमस मंदिरों में से एक है।

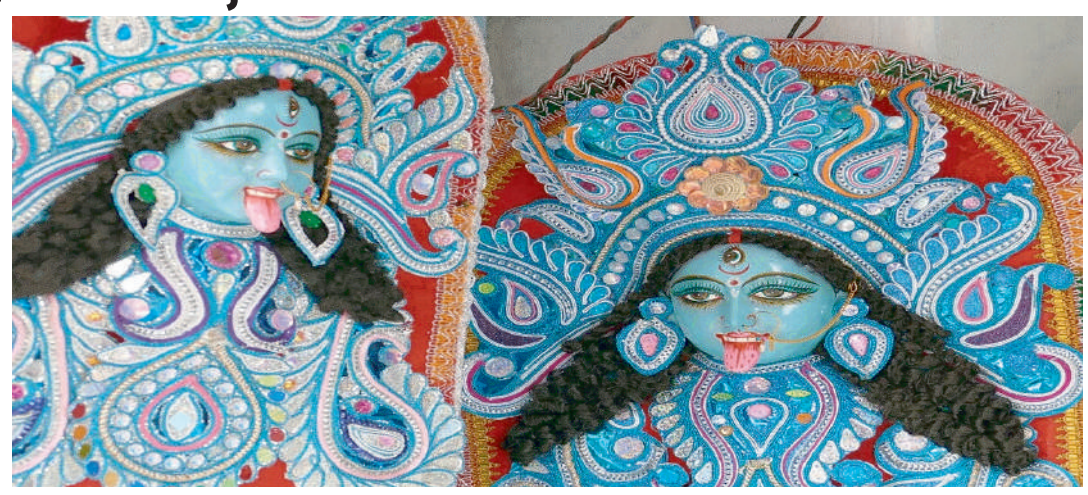

सर्दियों में डैंड्रफ के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है ये 5 हेयर ऑयल

सर्दी के दौरान डैंड्रफ की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। वातावरण में नमी के कारण स्कैल्प ड्राई होने लगता है। इस कारण से बालों में रूसी, खुजली और स्कैल्प ड्राई हो जाता है। इसको कम करने के लिए आप घर पर ही इन 5 तेलों को सिर पर लगा सकते हैं।

सर्दियों के दौरान बालों को लेकर के लिए काफी समस्याएं बढ़ने लगती है। इस मौसम में बालों की केयर ढंग से नहीं हो पाती और ऊपर से बालों में डैंड्रफ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बालों में रुसी, खुजली और स्कैल्प ड्राई होने लगता है। सर्दियों के मौसम में शरीर में नमी के कारण से सिर की त्वचा रुखी हो जाती है। डैंड्रफ से निपटने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है एंटी-डैंड्रफ हेयर ऑयल बालों में लगाएं, इसे आप घर परबना सकते हैं या फिर बाजार से खरीद सकते ।

नारियल तेल के साथ नींबू का रस

नारियल का तेल आपके घर में जरुर होगा। बता दें कि, नारियल का तेल लॉरिक एसिड से भरा होता है, जो रोगाणुरोधी गुण से भरपूर होता है। इसके साथ ही आप नारियल तेल के साथ नींबू मिलाकर जरुर लगाएं। यह हमारे बालों की जड़ों में पहुंचकर रुसी को नियंत्रित करता है।

टी ट्री ऑयल

टी ट्री के पत्तियों के भाप से डिस्टलेशन से बनाया जाता है। इसमें एंटीफंगल और एंटी-बैक्टीरिया के गुण होते हैं। इस तेल से सप्ताह में दो बार हल्की मालिश कर सकते हैं। सिर की त्वचा साफ होती है और घने बाल भी उगते हैं। बाजार में भी टी ट्री हेयर मिलते हैं, जिनका आप यूज कर सकते हैं।

थाइम हेयर ऑयल

थाइम एक जड़ी बूटी है जिसमें कुछ फूल वाले पौधों के सूखे एरिअल भाग में शामिल होते हैं। यह अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीफंगल और जीवाणुरोधी गुणों के लिए जाना जाता है। इसलिए, थाइम तेल की मदद से आप अपने सिर से रूसी, पपड़ी बनना, खुजली और अन्य फंगल संक्रमण को जड़ से खत्म होता है। बाजार में आपको यह हेयर ऑयल मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं।

रोजमैरी और पेपरमिंट ऑयल

डैंड्रफ की समस्या से बचने के लिए आप पेपरमिंट और रोजमैरी का ऑयल से मालिश करना सबसे बढ़िया है। इस हेयर ऑयल में सूजन-रोधी और एंटीफंगल के गुण होते हैं। यह आपकी खुजली को शांत कर सकते हैं।

लैवेंडर ऑयल

लैवेंडर ऑयल में शक्तिशाली एंटीफंगल गुण होते हैं। लैवेंडर तेल से सिर की मालिश करने से रक्त संचार बढ़ता है, रूसी कम होती है और सिर को शांति मिलती है।

कब से खरमास शुरु हो रहा है? जानें तिथि, उपाय और इसका महत्व

सनातन धर्म में खरमास का बेहद महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, खरमास साल में दो बार आती है और यह 30 दिनों तक चलती है। इन दिनों में शुभ कार्य नहीं होते। शादी से लेकर गृह प्रवेश के समारोह नहीं होते हैं।

साल में दो बार खरमास आता है। सनातन धर्म में खरमास का काफी महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक, यह 30 दिनों तक चलता है और इन दिनों में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। जैसे कि शादी, सगाई, गृहुप्रवेश समारोह या अन्य पवित्र अनुष्ठान आदि नहीं होते हैं। इस अवधि में भगवान सूर्य की पूजा करना शुभ होता है। भक्तों को सूर्य को जल चढ़ाने, वैदिक मंत्रों का जाप करने और आध्यात्मिक अभ्यास करना जरुरी होता है। आइए आपको खरमास के बारें इसकी जानकारी बताते हैं।

खरमास कब शुरू होगा ?

पंचांग के अनुसार, खरमास 15 दिसंबर, रविवार को रात 10.19 बजे शुरु होगा। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा। खरमास की यह अवधि मंगलवार, 14 जनवरी 2025 को समाप्त होती है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। इसके बजाय सूर्य देव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया अवधि है।

खरमास के दौरान अनुष्ठान और पूजा

सुबह की दिनचर्या

खरमास के समय भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठना चाहिए। इसके बाद स्नान करना चाहिए।

सूर्य देव को जल चढ़ाएं

स्नान के बाद ही आप उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। जल में लाल सिंदूर, चावल, गुड़ या लाल फूल जैसी सामग्री होनी चाहिए।

प्रार्थना और आरती करें

इसके बाद सूर्य देव से प्रार्थना करें और वैदिक मंत्रों का जाप करें। सूर्य चलीसा का पाठ करें। इसके साथ ही धूप, दीप और कपूर जलाएं और भगवान सूर्य की आरती करें।

प्रसाद अर्पित करें

सूर्य देव को भोग के रुप में फल और मिठाइयां जरुर अर्पित करें।

खरमास के दिन इन मंत्रों करें जाप

- ॐ ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्यः क्लीं ॐ

- सूर्य देव का गायत्री का मंत्र- ॐ आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात।

- मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्रकिरणराय मनोवांचित फलं देहि देहि स्वाहा।

उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाएं मलाई पेड़े का भोग, नोट करें सिंपल रेसिपी

हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का खास मौका है। इस शुभ दिन सभी भक्त व्रत रखकर भगवान को प्रिय भोग अर्पित करते हैं। ऐसे में अगर आप भी घर बैठे ही श्रीहरि को स्वादिष्ट भोग लगाना चाहते हैं तो यहां हम आपके लिए मलाई पेड़े की आसान रेसिपी लेकर आए हैं।

उत्पन्ना एकादशी जो हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत रखने और भगवान को मिष्ठान का भोग लगाने से धन, समृद्धि और सुख-शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे में, इस खास मौके पर आप भगवान विष्णु को मलाई पेड़े का भोग (Lord Vishnu Bhog) लगा सकते हैं, जो उन्हें बेहद प्रिय है। आइए जानते हैं मलाई पेड़ा बनाने की आसान-सी विधि।

उत्पन्ना एकादशी का भोग

मलाई पेड़े बनाने के लिए सामग्री

दूध- 1 लीटर (फुल फैट मिल्क)

चीनी- 1 कप

इलायची पाउडर- 1/2 चम्मच

केसर- कुछ धागे (दूध में भिगोकर)

सूजी- 2 बड़े चम्मच

देसी घी- 1 बड़ा चम्मच

बादाम- कटे हुए, गार्निशिंग के लिए

पिस्ता- कटे हुए, गार्निशिंग के लिए

मलाई पेड़े बनाने की विधि

सबसे पहले एक भारी तले वाले पैन में दूध डालें और मध्यम आंच पर उबाल लें। लगातार चलाते रहें ताकि दूध नीचे लग न जाए। जब दूध आधा रह जाए तब गैस बंद कर दें।

इसके बाद गाढ़े हुए दूध में चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

अब सूजी को थोड़े से पानी में घोलकर दूध में डालें और लगातार चलाते रहें।

फिर मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा और एकत्रित होने लगे।

अब केसर के धागों को दूध में भिगोकर रखें और फिर इस मिश्रण में डाल दें।

इसके बाद छोटे-छोटे पेड़े बनाकर गर्म देसी घी में सुनहरा होने तक तल लें।

पेड़ों को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें।

आखिर में, ठंडे पेड़ों को बादाम और पिस्ता से सजाएं।

स्पेशल टिप्स

मलाई पेड़े को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इसमें थोड़ी मात्रा में खोया भी मिला सकते हैं।

अगर आप मलाई पेड़े को ज्यादा नरम बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और मिला सकते हैं।

पेड़ों को ज्यादा समय तक ताजा रखने के लिए आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं।

सेहत के लिए भी फायदेमंद

मलाई पेड़ा दूध से बना होता है जो कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है।

इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को एनर्जी देता है।

इलायची पाउडर पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है।

दिल्ली के प्रदूषण से तंग हो गए हैं, तो इन प्राकृतिक जगहों पर जरुर घूमने जाएं

इस समय भारत के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर 1000 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से बहुत बुरा हाल हो रखा है। जहरीली हवा से अगर आपका भी दम घुट रहा है तो आप बाहर घूमने के लिए इन जगहों पर जरुर जाएं। यहां हवा एकदम साफ होगी और सुंदर प्राकृतिक नजारे देखने को मिलेंगे।

भारत के कई हिस्सों में इस समय प्रदूषण से बुरा हाल हो रखा है। जहरीली हवाओं में रह-रह कर जीना दुश्वार हो जाता है। दिल्ली के आसपास इलाकों में एक्यूआई लेवल 1000 के पार पहुंच गया है। इस दौरान अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भारत की इन जगहों पर जरुर जाएं। यहां पर आप प्रदूषण न के बराबर मिलेगा। यहां आप खुलकर सांस ले सकते हैं।

आइजोल

अगर आप शांत और सुकून से भरे जगह की तलाश में हैं तो आप इन परफेक्ट जगहों पर जरुर जा सकते हैं। खूबसूरत पहाड़ियों और घाटियों से घिरा ये शहर आपका का मन मोह लेगा। यहां की खूबसूरती और प्राकृतिक नजारे देखकर आपका मन खुश रहेगा।

मैंगलोर

दक्षिण भारत में घूमने के लिए कई शानदार जगहें है। यदि आप घूमने फिरना पसंद है तो आप मैंगलोर को अपनी लिस्ट में जरुर शामिल करें। यहां आप बीच के साथ ही प्राचीन मंदिर घूम सकते हैं। यहां आपको अलग आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा।

गंगटोक

सिक्किम में मौजूद गंगटोक शहर बेहद ही खूबसूरत है। यहां पर घूमने का लिहाज से काफी आकर्षक, प्राकृतिक और बादलों से घिरी हुई शानदार जगह। इस पॉल्यूशन फ्री शहर में आप मजे कर सकते हैं।

कोल्लम

केरल में तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट में करीब 80 किमी दूर कोल्लम शहर बेहद ही खूबसूरत है। यहां पर शांति से भरा वातावरण देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप प्रचीन इतिहास और आधुनिक लाइफस्टाइल जरुर देख सकते हैं।

भारत में हर साल 20 लाख लोग समय से पहले मर रहे, प्रदूषण सबसे बड़ा कारण; GRAP भी कोई समाधान नहीं

भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिससे हर साल लगभग 20 लाख लोग समय से पहले मौत के शिकार हो रहे हैं। आईआईटी कानपुर में स्थापित आत्मन सेंटर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए काम कर रहा है। इस केंद्र ने वायु प्रदूषण के स्त्रोतों की पहचान करने के लिए एक सस्ता और त्वरित परिणाम देने वाला सिस्टम विकसित किया है।

नई दिल्ली। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत के गंगा-यमुना क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। इन दिनों दिल्ली और एनसीआर में तो सांस लेना भी दूभर हो रहा है। स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है कि वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या की वजह से भारत में हर साल लगभग 20 लाख लोग समय पूर्व मृत्यु के शिकार हो रहे हैं।

इससे बचाव के लिए आईआईटी कानपुर में आत्मन (एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फार एयर क्वालिटी आई इंडिकेटर) उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। यह केंद्र उप्र व बिहार के 1400 विकास खंडों में स्थापित निगरानी उपकरणों से वायु गुणवत्ता का डाटा एकत्र कर रहा है। फिर एआई की मदद से विश्लेषण कर वायु गुणवत्ता में सुधार का माडल विकसित कर रहा है।

आईआईटी में कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनबिलिटी की स्थापना भी गई है, जो शहरों के लिए टिकाऊ जीवन शैली का मॉडल विकसित करेगा। इन दोनों केंद्रों को स्थापित करने में आत्मन सेंटर के प्रमुख और कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनबिलिटी के डीन प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी की अहम भूमिका है। वह मानते हैं कि आपात स्थिति में ग्रेप लागू करने से प्रदूषण का समाधान नहीं होगा।

मूलतः वाराणसी के रहने वाले प्रो. त्रिपाठी ने आईआईटी बीएचयू से बीटेक की डिग्री ली है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। वर्ष 2014 में पृथ्वी, वातावरण, समुद्र और ग्रह विज्ञान क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें प्रतिष्ठित शांतिस्वरूप भटनागर अवार्ड दिया गया। वह कई राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के फेलो भी हैं। दैनिक जागरण के संवाददाता अखिलेश तिवारी ने उनसे विस्तृत बातचीत की...

समूचे उत्तर भारत में इस बार भी वायु प्रदूषण के संकेत चिंताजनक हैं। आत्मन सेंटर की रिपोर्ट क्या कह रही है?

यह सही है कि इस साल भी नवंबर के पहले सप्ताह में वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। यह गिरावट पूर्वी पाकिस्तान से लेकर गंगा बेसिन के भीतरी हिस्से तक देखी गई है। अक्टूबर तक का डाटा बताता है कि भारत के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आग लगने की घटनाएं कम हुई हैं। इसके पहले के वर्षों में ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा हुआ करती थीं। पिछले दस साल में केंद्र सरकार की ओर से जो प्रभावी कदम उठाए गए हैं, उससे स्थिति सुधरी है। कमीशन फार एयर क्वालिटी मेजरमेंट जैसी संस्थाओं का गठन करने से लाभ मिला है। इसके बावजूद अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक दो दिन के लिए भी 400 के ऊपर जा रहा है तो यह अत्यधिक चिंताजनक है।

वायु प्रदूषण व मौसम का क्या रिश्ता है?

वायु प्रदूषण और मौसम प्रभाव पर देश में लंबे समय से चर्चा हो रही है, लेकिन अभी विदेश में कई अच्छे शोध कार्य हुए हैं, जिनसे साबित हो गया है कि वायु प्रदूषण का मौसम पर सीधा असर पड़ रहा है। वायु प्रदूषण बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है और इससे मौसम में तीव्र बदलाव हुए हैं। अचानक और अत्यधिक सर्दी या वर्षा अथवा गर्मी हो रही है। अचानक जब मौसम तेजी से सर्द हो जाता है तो इसका असर वायु प्रसार क्षमता पर पड़ता है।

इससे पृथ्वी की सतह से उठने वाली हानिकारक गैसों को ऊपर जाने का मौका नहीं मिलता और वह वायुमंडल के निचले स्तर पर एकत्र होने लगती हैं। मौसम अक्टूबर-नवंबर में तेजी से बदलता है। इससे वायु प्रदूषण की स्थितियों को समर्थन मिलता है।

वायु प्रदूषण के सूचकांक के आधार पर क्या प्रदूषणकारी लोग, यानी उद्यम या कार्यक्षेत्र की पहचान की जा सकती है?

हवा कणों में मौजूद रसायनों का विश्लेषण करने से उद्यम या कार्यक्षेत्र की पहचान की जा सकती है, लेकिन इस जांच का जो पारंपरिक तरीका है उसमें दो से ढाई साल का समय लगता है। जांच प्रक्रिया भी बेहद खर्चीली है। आईआईटी में स्थापित आत्मन सेंटर ने इसका सस्ता और त्वरित परिणाम देने वाला सिस्टम विकसित किया है, जिसके तहत मोबाइल लैब की मदद से 10 दिन में परिणाम पाया जा सकता है। इस विधि से वायु में मौजूद जैविक प्रदूषण की पहचान भी संभव हो गई है जो भारत के संदर्भ में अत्यंत आवश्यक है।

मोबाइल लैब की स्थापना में भी अधिक खर्च है, इसे कम करने के लिए सेंसर का प्रयोग किया गया है, जिससे कुछ लाख रुपये खर्च करके एआइ आधारित सेंसर से डाटा मिलने लगा है। अब यह पता करना आसान हो गया है कि किसी भी शहर में कब और किस क्षेत्र से किस तरह का वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। प्रदूषण की प्रकृति भी पहचानी जा सकती है। भविष्य में प्रशासन व शासन में बैठे लोग अपने राज्य व शहरों की प्लानिंग करने में भी इसकी मदद ले सकेंगे और प्रदूषण नियंत्रण के ठोस कदम उठाने आसान होंगे।

वायु प्रदूषण की मौजूदा स्थिति से निपटने में क्या मौजूदा नियंत्रणकारी उपाय, नीतियां प्रभावी हैं? या नए उपायों की जरूरत है?

वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीतियां लाई गई हैं, लेकिन उनका कारगर अनुपालन अभी बाकी है। हमारे पास अभी वायु प्रदूषण का समग्र डाटा उपलब्ध नहीं है। इसे मापने के लिए जो सिस्टम प्रयोग किया जा रहा है वह विदेशी उपकरणों पर आधारित है। बहुत महंगा होने की वजह से पूरे देश के वायु प्रदूषण की तस्वीर सामने नहीं आ रही है। एयरशेड के स्तर पर विश्लेषण की जरूरत है।

सीजन के अनुसार, बड़े एयरशेड और माइक्रो एयरशेड कैसे हैं। उनकी जानकारी मिलने पर ही नियंत्रण उपायों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। ड्रोन इंटीग्रेटेड सेंसर के साथ अपने निगरानी सिस्टम को व्यापक बनाना होगा। शिक्षण संस्थानों में भी हमें वायु गुणवत्ता संबंधी तकनीक की शिक्षा देने की जरूरत है, जिससे ऐसे इंजीनियर व तकनीशियन मिल सकें जो निगरानी सिस्टम का हिस्सा बनकर काम करें।

कहा जाता है कि औद्योगीकरण और वायु प्रदूषण का चोली-दामन वाला रिश्ता है, यानी अधिक उद्योग और अधिक पर्यावरण को नुकसान। क्या बचने का कोई तरीका है?

औद्योगीकरण अत्यंत आवश्यक है। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए उद्योगों को संचालित करना ही होगा, लेकिन इसके लिए हमें प्रदूषण नियंत्रण नियामक व्यवस्था को प्रभावी बनाना होगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया से सीखने की जरूरत है। वहां तीव्र औद्योगीकरण हुआ। उन्होंने 50 साल पहले कैलिफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्ड बनाया।

उनकी भौगोलिक स्थिति भी इंडो गैंजेटिक रीजन की तरह ही है। इस बोर्ड में आज 2200 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिनमें इंजीनियर, साइंटिस्ट, तकनीशियन और लीगल एडवाइजर हैं, जो नियमों का उल्लंघन कराने वालों को अदालत में दंड दिलाते हैं। इसका असर हुआ कि तीव्र विकास के बावजूद वहां प्रदूषण नियंत्रित अवस्था में है।

क्या कूड़ा प्रबंधन में विफलता भी पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा रहा है?

कूड़ा प्रबंधन की दिशा में पूरे देश में अभी बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। कोटक स्कूल आफ सस्टेनबिलिटी और कानपुर नगर निगम मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोग एक माडल विकसित करने की कोशिश में है, जिससे शहर को कूड़ा मुक्त व्यवस्था मिल सके। कूड़ा प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। यह कूड़ा स्थलों की भूमि को प्रदूषित करने के साथ ही हानिकारक ओजोन गैस मिथेन का प्रमुख स्रोत है। कूड़ा या पराली जलाने से तो पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है।

ऐसा लग रहा है कि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट अकेले लड़ाई लड़ रहा है? हम लोग साल दर साल शीर्ष अदालत में एक जैसी सुनवाई के आदी होते जा रहे हैं?

प्रदूषण के खिलाफ जंग में सुप्रीम कोर्ट की निरंतर और प्रभावी भूमिका है, लेकिन मेरा मानना है कि समाचार माध्यमों ने पिछले कई दशक के दौरान ऐसा वातावरण निर्मित किया है, जिससे सभी संस्थाओं का ध्यान इस समस्या की ओर गया है। जैसा मैंने पहले कहा कि पिछले सात साल से वायु गुणवत्ता सूचकांक में उत्तरोत्तर सुधार दिख रहा है। यह संकेत है कि समाज व देश का नजरिया प्रदूषण के प्रति बदल रहा है।

वायु प्रदूषण के कारण आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है?

वायु प्रदूषण का आर्थिकी पर ठीक-ठाक असर पड़ता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि जब विकास होगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, लेकिन आज के दौर में ऐसा कहना उचित तर्क नहीं है। आज हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने पर्यावरण को संरक्षित करते हुए विकास का लक्ष्य हासिल किया है।

सड़क, भवन व पुल निर्माण के कार्यों से भी वायु प्रदूषण अधिक होता है, क्या अधिक टिकाऊ सड़कों का निर्माण विकल्प है?

निर्माण कार्यों में हमें गुणवत्ता पर अधिक जोर देने की जरूरत है। अगर टिकाऊ निर्माण होगा तो बार-बार निर्माण की जरूरत नहीं होगी। इससे प्रदूषण में कमी आएगी। निर्माण के समय अगर सभी मानकों का पालन किया जाए तो प्रदूषण को न्यूनतम करने में सफलता मिलेगी। सड़कों की इंजीनियरिंग ऐसी हो, जिससे वह बार-बार नहीं टूटे। इससे बार-बार निर्माण के समय होने वाला प्रदूषण कम होगा और टूटी सड़कों पर वाहनों के चलने से जो अधिक प्रदूषण होता है वह भी कम हो जाएगा।

परिवहन साधनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए, भारत में वाहनों की संख्या हर साल तेजी से बढ़ रही है, इसे भी वायु प्रदूषण का बड़ा कारण माना जाता है?

सामुदायिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके प्रयोग के लिए सभी को प्रेरित किया जाए। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाए। विश्व के कई देशों ने ऐसा किया है। निजी वाहनों का प्रयोग कम से कम हो ऐसी व्यवस्था लागू करने की जरूरत है। बड़े टूर ऑपरेटर, स्कूल वाहनों को सीधे इलेक्ट्रिक वाहनों पर डाल दिया जाए।

क्या एनसीआर के साथ पूरे इंडो गैंजेटिक क्षेत्र में पड़ने वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में भी ग्रेप लागू करने से प्रदूषण में कमी आ सकती है?

ग्रेप को कई बार लागू किया गया, लेकिन इसके वैसे फायदे नहीं हैं, जैसी आवश्यकता है। जब हम आपात स्थिति में कोई उपाय लागू करने के बारे में सोचेंगे तो समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। देखिए, एक बात ध्यान रखें कि वायु गुणवत्ता एक प्रबंधन से जुड़ी स्थिति है। इस समस्या का कभी पूरी तरह से समाधान नहीं मिलता, क्योंकि अर्थतंत्र अत्यधिक विविधता वाला है। इसलिए हमारा रिस्पांस भी डायनमिक होना चाहिए। हमारा प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि ज्यादातर समय वायु गुणवत्ता अच्छी रहे। 365 में 340 या 345 दिन वायु गुणवत्ता अच्छी रहनी ही चाहिए। इसलिए प्रबंधन भी वैसा ही करने की जरूरत है।

प्रदूषण दूर करने का पूरा जिम्मा सरकार पर थोपना कहां तक उचित है? क्या सामुदायिक जिम्मेदारी का भी कोई माडल हो सकता है?

प्रदूषण के लिए किसी एक पर जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं है। सभी को मिलकर काम करना होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि जब समाचार माध्यमों ने जागरूकता का माहौल बनाया तो नागरिकों से लेकर प्रशासन व शासन सभी का सोच बदला और सकारात्मकता बढ़ी है। प्रदूषण की समस्या पर अब आम नागरिक से लेकर अधिकारी व न्यायपालिका तक सभी वर्ग संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं।

एक विज्ञानी एवं चिंतक के रूप में आपको क्या लगता है कि प्रदूषण से लड़ाई में हम कहां हार रहे हैं?

प्रदूषण की स्थितियों में पिछले सात-आठ साल में निरंतर सुधार हुआ है। हालांकि यह सुधार आवश्यकता से बहुत कम है। फिर भी उम्मीद है कि आगे और तेजी से प्रयास किए जाएंगे। वायु गुणवत्ता के हाई क्वालिटी डाटा मिलने से ठोस उपाय लागू करना आसान हो जाएगा। जैसा दिख रहा है कि पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आई है। नागरिक और सरकार सभी स्तर पर जागरूकता बढ़ी है जो आशाजनक है।

भारत में प्रदूषण का मानव की कार्यक्षमता पर क्या असर पड़ रहा है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए अध्ययन के अनुसार, फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, इससे भी कहीं ज्यादा यह पता चला है कि मानव की कुल कार्यक्षमता पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, जो भारत में तीन सप्ताह से लेकर एक महीने तक की कार्यक्षमता घट रही है। मानसिक स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशुओं पर घातक असर का आकलन किया जा रहा है। प्रदूषण की वजह से एक अनुमान है विश्व में प्रतिवर्ष 80 से 90 लाख लोग समय पूर्व मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। भारत में भी यह संख्या 20 लाख तक पहुंच चुकी है।

'45 दिन में सुधारो कानून-व्यवस्था', दिल्ली पुलिस को अमित शाह की दो टूक; कहा- डेढ़ माह बाद फिर करूंगा मीटिंग

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की लचर कानून व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पुलिस आयुक्त समेत कई आला अधिकारियों को तलब कर फटकार लगाई और 45 दिन में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है सरेआम गोलियां चल रही हैं और गैंगस्टरों का आतंक है। उन्होंने स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को मजबूत बनाने पर जोर दिया है।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस आयुक्त समेत दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारियों को गृह मंत्रालय बुलाकर लचर कानून व्यवस्था को लेकर जमकर खिंचाई करते हुए जल्द हालात में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आतंकवाद निरोधक दस्ता स्पेशल सेल व क्राइम ब्रांच की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए इन यूनिटों को नए सिरे से मजबूत बनाने पर बल दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए इन यूनिटों को मजबूत बना पाना बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए 45 दिन की मोहलत दी और डेढ़ माह बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही।

राजधानी में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सेल व क्राइम ब्रांच को मजबूत बनाने की जरूरत है तभी गैंगस्टरों के आतंक पर काबू पाया जा सकता है। हाल के महीनों में राजधानी में बेतहाशा बढ़ते अपराध पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा सवाल उठाने पर गृह मंत्री ने शुक्रवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए दिली पुलिस के अधिकारियों को गृह मंत्रालय तलब किया था।

'मुझे सब पता है...'

बैठक में एक विशेष आयुक्त ने जब प्रजेंटेशन देना शुरू किया, तब गृह मंत्री ने कहा कि प्रजेंटेशन देने से काम नहीं चलेगा। दूसरे विशेष आयुक्त ने जब प्रजेंटेशन देना शुरू किया तब गृह मंत्री ने उनकी भी प्रजेंटेशन देखने से मना कर दिया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे सब कुछ पता है कि दिल्ली पुलिस में क्या-क्या हो रहा है।

भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है- शाह

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सरेआम गोलियां चल रही हैं, गैंगस्टरों में रंगदारी वसूलने की होड़ लगी हुई है। बदमाश अवैध हथियार व चाकू लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं, लोग दहशत में जी रहे हैं। उन्होंने तुरंत राजधानी की कानून व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए और 45 दिन बाद रिपोर्ट पेश करने को कहा।

बाद में डीसीपी ने बलाई बैठक

गृह मंत्री के निर्देश के बाद शनिवार को सभी 15 जिले के डीसीपी ने अपने-अपने जिले में सभी थानों के इंस्पेक्टरों की बैठक बुलाई। उन्हें बदमाशों, झपटमारों व ड्रग्स तस्करों समेत अवैध हथियार व चाकू लेकर घूमने वालों की धर पकड़ तेज करने और गैंगवार की घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

स्पेशल सेल की कुछ अधिकारियों ने गिराई साख

मुख्यालय सूत्रों की मानें तो स्पेशल सेल में कुछ अधिकारियों की मनमानी के कारण सेल की साख गिर गई है। सेल की टीम पूरी तरह बिखर चुकी है। इसी माह सेल के मुखिया विशेष आयुक्त आरपी उपाध्याय सेवानिवृत्त होंगे।

ऐसे में नए मुखिया के लिए वैसे तो तीन चार विशेष आयुक्त के नाम की चर्चा है, लेकिन अगर 1991 बैच के अधिकारी विवेक गोगिया को सेल की जिम्मेदारी मिला तब सेल को पहले की तरह मजबूत बनाने की दिशा में बेहतर कदम माना जा रहा है। गोगिया बहुत ही सख्त व इमानदार आइपीएस माने जाते हैं। इन्हें सेल में लाने पर कुछ अधिकारियों की मनमानी तुरंत खत्म हो सकता है।

तो फिर नहीं सुधर पाएंगे सेल के हालत

गोगिया को सेल की जिम्मेदारी नहीं मिलने पर सेल की स्थिति में सुधार ला पाना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। हालांकि गोगिया का कार्यकाल आठ माह ही बचा हुआ है। गोगिया के अलावा किसी अन्य को जिम्मेदारी मिलने पर कुछ अधिकारी अपनी मनमानी जारी रख सकते हैं। ऐसे में दो माह में सेल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। नई दिल्ली रेंज को एक नया डीसीपी मिल सकता है, क्योंकि इस रेंज की प्रभारी प्रतीक्षा गोदारा को पदोन्नत किया जा रहा है।

प्रणव तायल को भी पदोन्नत किया जा सकता है। गोदारा पहले हरियाणा में कार्यरत थे। सूत्रों के मुताबिक गोदारा और तायल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर बनने पर वर्तमान अतिरिक्त आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाह को यूनिट से बाहर किए जाने की संभावना है।

डीसीपी मनीषी चंद्रा का क्या होगा?

डीसीपी मनीषी चंद्रा जो वर्तमान में सेल में महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, उन्हें आईपीएस में शामिल किया जाएगा। यदि उन्हें दिल्ली से बाहर नहीं भेजा जाता है तब वे एकमात्र डीसीपी बने रहेंगे। पहले सेल में डीसीपी के रूप में दानिप्स-काडर के अधिकारियों को ही प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने सेल में आईपीएस अधिकारियों को तैनात करने का चलन शुरू किया, ताकि यूनिट पर बेहतर नियंत्रण हो सके, जिसके बाद से ही सेल में गिरावट जारी है। सेल ने सादिक नगर में एक नए मुख्यालय में शिफ्ट होना भी शुरू कर दिया है। सेल की लोधी कालोनी को वहां शिफ्ट किया जा सकता है।

भाजपा दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मांगेराम गर्ग के जन्म जयंती पर सेवा कार्य कर दी श्रद्धांजलि

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मांगेराम गर्ग को उनके जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।

इस अवसर पर हवन, भंडारा व दीपचंद बंधु अस्पताल अशोक विहार में फल वितरण किया गया।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री व सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि मांगेराम गर्ग श्रेष्ठतम सेवा व्रती थे, वे बाल काल में समालखा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाना हो या फिर युवावस्था में विनोवा भावे के सानिध्य में स्वालंबन आंदोलन में अग्रणी भूमिका के रूप में कार्य करते हुए घरों से शौच साफ करना, प्रौढ़ावस्था में समाज व राष्ट्र के सर्वांगीण विकास हेतु सैकड़ों संस्थाओं का सृजन, समाज हित में सदैव समर्पित रहने का भाव जीवंत उदाहरण है।

उनका जीवन एकाग्रता और निष्ठा से परिपूर्ण समाज और राष्ट्र के कल्याण, उन्नति और विकास के लिए समर्पित रहा। बाऊजी श्रेष्ठ संगठक थे। उनके नेतृत्व में दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर पहली बार हमने विजय का परचम फहराया। उन्होंने अपने सुक्ष्म प्रबंधन कला से दिल्ली में बुथ समिति के कार्यकर्ताओं को प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति के दुख सुख का सहभागी होने की प्रेरणा दी।

सतीश गर्ग कोषाध्यक्ष भाजपा दिल्ली प्रदेश ने बाऊजी को प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम में जिला केशव पुरम भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, डॉ महेंद्र नागपाल, योगेश वर्मा, अजय खटाना, देवराज, अजय शर्मा, सुरेश भारद्वाज, उमाकांत, प्रवेश टोनी, गीता गुलाटी समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित हुए।

दिल्ली का लगातार वायु प्रदूषण संकट

दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए निवारक उपाय स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है जैसे सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन पर स्विच करना वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, सभी डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को 2023 तक अपने बेड़े का 50% और 2025 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। किसानों को बायो-डीकंपोजर और नो-बर्न तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने से पराली जलाने में कमी आ सकती है। महाराष्ट्र में सगुना चावल तकनीक पराली जलाने को कम करती है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ाने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे उत्सर्जन पर अंकुश लग सकता है। दिल्ली मेट्रो चरण।V का विस्तार कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात से सम्बंधित प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखता है। पूसा द्वारा विकसित बायोडीकंपोजर का उपयोग पराली प्रबंधन के महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक है।

-डॉ सत्यवान सौरभ

भारत अपने विषैले धुएँ को साफ़ करने में क्यों विफल रहा है? राज्य के अधिकारी एक त्रायोगिक योजना का प्रचार करते हैं जिसमें बारिश के लिए बादलों को उत्तेजित करना शामिल है, लेकिन वैज्ञानिक संशय में हैं। तकनीकी प्रगति और नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद दिल्ली को अक्सर दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर 2024 में, वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर को पार कर गया, जो कुछ क्षेत्रों में 500 तक पहुँच गया, जो 400 की "गंभीर" सीमा से कहीं अधिक है। यह भयावह स्थिति शहर के बढ़ते प्रदूषण संकट से निपटने के लिए प्रभावी, दीर्घकालिक समाधानों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। सामान्य वायु प्रदूषण भारत में अपनी आधी से अधिक बिजली बनाने के लिए कोयले को जलाने से जुड़ा है। दिल्ली में, यह लाखों कारों से होने वाले उत्सर्जन और निर्माण उद्योग से निकलने वाले धुएँ के साथ मिलकर काम करता है, जहाँ कोई प्रदूषण नियंत्रण नहीं है।

कुछ लोग अक्टूबर के अंत में हिंदू रोशनी के त्यौहार दिवाली के दौरान पटाखों के व्यापक उपयोग को भी इसके लिए दोषी ठहराते हैं। अधिकारियों ने 2017 में पारंपरिक पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था और लोगों को केवल पर्यावरण के अनुकूल रोशनी का उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन नियम को ठीक से लागू नहीं किया गया।पीएम2.5, प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण पदार्थ, फेफड़ों में गहराई तक जाकर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, ख़ासकर बच्चों, बुज़ुर्गों और श्वसन या हृदय की स्थिति वाले लोगों के लिए। हर साल, भारत में श्वसन सम्बंधी बीमारियों से सैकड़ों हज़ार लोग मरते हैं। 2021 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में पाया गया कि भारत का कोई भी शहर प्रति घन मीटर हवा में 5 माइक्रोग्राम पीएम2.5 के अद्यतन विश्व स्वास्थ्य संगठन सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता है। भारत के लगभग आधे राज्य इस सीमा को 10 गुना से भी ज़्यादा पार कर गए हैं।

तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और निजी वाहनों की बढ़ती संख्या कण पदार्थ उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सफ़र इंडेक्स से पता चलता है कि वाहन प्राथमिक प्रदूषक हैं, जो पीएम2.5 उत्सर्जन में लगभग 40 प्रतिशत और नाइट्रोजन ऑक्साइड में 81 प्रतिशत का योगदान करते हैं। पुरानी तकनीक और उचित उत्सर्जन नियंत्रण की कमी के कारण दिल्ली और इसके आसपास के उद्योग ज़हरीली गैसें छोड़ते हैं। एनजीटी ने सीपीसीबी द्वारा प्रस्तुत क्षमता रिपोर्ट के आधार पर जिगज़ैग तकनीक वाले ईंट भट्टों सहित सभी ईंट भट्टों को बंद करने का निर्देश दिया है। पंजाब और हरियाणा में फ़सल अवशेषों को जलाने से दिल्ली की हवा में भारी मात्रा में धुआं और कण निकलते हैं। एनसीआर में चल रही निर्माण परियोजनाओं से अपर्याप्त नियंत्रण उपायों के कारण बड़ी मात्रा में धूल उत्पन्न होती है। राजमार्गों और मेट्रो लाइनों के निर्माण से परियोजना निष्पादन के दौरान पीएम10 के स्तर में वृद्धि हुई है। भारत-गंगा के मैदान में दिल्ली का स्थान और सर्दियों के दौरान कम हवा की गति प्रदूषकों को फंसाती है, जिससे घने धुएँ की परत बनती है।

दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए निवारक उपाय स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है जैसे सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन पर स्विच करना वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, सभी डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को 2023 तक अपने बेड़े का 50% और 2025 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। किसानों को बायो-डीकंपोजर और नो-बर्न तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने से पराली जलाने में कमी आ सकती है। महाराष्ट्र में सगुना चावल तकनीक पराली जलाने को कम करती है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ाने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे उत्सर्जन पर अंकुश लग सकता है। दिल्ली मेट्रो चरण।V का विस्तार कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात से सम्बंधित प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखता है। पूसा द्वारा विकसित बायोडीकंपोजर का उपयोग पराली प्रबंधन के महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक है।

निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन जैसे धूल दबाने वाले पदार्थों के इस्तेमाल को अनिवार्य करना। 2021 की सर्दियों के दौरान, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आपातकालीन उपायों की एक शृंखला शुरू की, निर्माण पर प्रतिबंध लगाया, तीव्र धूल नियंत्रण उपायों को लागू किया। हरित स्थानों का विस्तार करना और सड़कों के किनारे पेड़ लगाना प्राकृतिक वायु शोधक के रूप में कार्य कर सकता है। नगर वन योजना एनसीआर उप-क्षेत्रों में हरियाली के लिए एक अवसर है। दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्मॉग टावर लगाने से स्थानीय स्तर पर प्रदूषक स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। कॉनॉट प्लेस के स्मॉग टावर ने प्रदूषण के चरम समय के दौरान वायु गुणवत्ता में स्थानीय सुधार दिखाया है। वास्तविक समय प्रदूषण निगरानी सेंसर जैसे उन्नत निगरानी उपकरण लक्षित हस्तक्षेपों के लिए सटीक डेटा प्रदान कर सकते हैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली की वायु गुणवत्ता संकट को दूर करने के लिए अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देता है।

पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं पर जनता को शिक्षित करना, जैसे कि वाहनों को निष्क्रिय रखना, प्रदूषण के स्तर को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। "रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ" जैसे अभियान उत्सर्जन को कम करने के लिए व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। सामान्य वायु प्रदूषण भारत में कोयले को जलाने से जुड़ा है, जिससे इसकी आधी से ज़्यादा बिजली पैदा होती है। दिल्ली में, यह लाखों कारों से निकलने वाले उत्सर्जन और निर्माण उद्योग से निकलने वाले धुएँ के साथ मिलकर होता है, जहाँ प्रदूषण नियंत्रण नहीं है। अक्टूबर से जनवरी तक यह संकट और गहरा जाता है, जब ठंड के मौसम के साथ-साथ बड़े पैमाने पर फ़सल के ठूंठ जलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के पड़ोसी राज्यों से धुआँ आता है, क्योंकि हज़ारों किसान फ़सल के मौसम के बाद कृषि अपशिष्ट जलाते हैं। हालाँकि, सर्दियों की भारी हवा प्रदूषकों को ज़मीन के करीब फँसा देती है, जिससे धुआँ और भी खराब हो जाता है।

हर वर्ग के मतदाताओं ने किया भाजपा पर भरोसा, जानिए कहां मुरझाया कमल; बीजेपी ने 17 साल पर चला था ऐसा दांव

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत संजीव शर्मा ने 69 हजार से अधिक मतों से जीत हासिल की। विजयनगर में योगी आदित्यनाथ के रोड शो के बाद बीजेपी को और मजबूती मिली। अनुसूचित वर्ग के मतदाताओं ने भी बीजेपी पर भरोसा जताया। संजीव शर्मा को कुल 96878 वोट मिले जबकि दूसरे नंबर पर रहे सपा प्रत्याशी सिंह राज जाटव को 27574 वोट मिले।

गाजियाबाद। उपचुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत की वजह कार्यकर्ताओं का सक्रिय रहना और पार्टी के समर्थित लोगों से मतदान कराना रहा। सभी वर्ग के मतदाताओं का साथ भाजपा को मिला है। यही वजह रही कि अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बहुत कम वोट मिलने के बावजूद भाजपा प्रत्याशी ने 69 हजार से अधिक मतों से जीत हासिल की है।

उपचुनाव में सबसे अधिक मतदान विजयनगर ए- ब्लॉक स्थित चिल्ड्रेंस एकेडमी स्कूल में हुआ था। इस बूथ पर भाजपा प्रत्याशी को सर्वाधिक वोट भी मिले हैं। उन्होंने यहां पर तिहरा शतक लगाया है।

विजयनगर में ही योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया था, जिसके बाद भाजपा खुद को चुनाव में और मजबूत मानकर चल रही थी। विजयनगर के अधिकतर बूथों पर भाजपा ने भारी अंतर से जीत हासिल की है।

सपा के सिंह राज को पूनम ने भी हराया

एसएसके पब्लिक स्कूल में बने बूथ संख्या 174 पर भी भाजपा को 304 वोट मिले हैं, यहां पर दूसरे नंबर पर हिंदुस्थान निर्माण दल की पूनम को 63 वोट मिले, वह दूसरे नंबर पर रहीं। सपा प्रत्याशी को यहां पर 53 और बसपा प्रत्याशी को 13 वोट मिले।

अनुसूचित वर्ग के लोगों ने भी किया भाजपा पर भरोसा

अनुसूचित वर्ग के मतदाताओं ने भाजपा पर भरोसा जताया है। यहां पर शिब्बनपुरा में मंत्री असीम अरुण गए थे। शिब्बनुपरा में बूथ संख्या 321 पर बसपा को 39, भाजपा को 42, सपा को आठ, आजाद समाज पार्टी को 24 वोट मिले। इनके अलावा अन्य प्रत्याशियों को इस बूथ पर एक भी वोट नहीं मिला है।

रिकॉर्ड वोटों से सीते भाजपा प्रत्याशी

गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा ने कम मतदान होने के बावजूद 69,304 वोटों से रिकॉर्ड जीत हासिल कर भाजपा को इस सीट पर जीत की हैट्रिक दिलाई है। संजीव शर्मा को कुल 96,878 वोट मिले हैं।

दूसरे नंबर पर रहे सपा प्रत्याशी सिंह राज जाटव को 27,574 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर रहे बसपा प्रत्याशी पीएन गर्ग की जमानत जब्त हो गई है, उनको कुल 10,729 वोट मिले हैं। चुनाव के मैदान में 14 प्रत्याशी उतरे थे। इनमें से 12 की जमानत जब्त हो गई है।

17 साल बाद भाजपा ने बनाया था ब्राह्मण प्रत्याशी

भाजपा ने 17 साल बाद इस सीट पर ब्राह्मण वर्ग से आने वाले संजीव शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले आखिरी बार वर्ष 2007 में इस सीट से सुनील शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया था, उन्होंने इस सीट पर भाजपा को जीत दिलाई थी। इसके बाद 2012 में सुनील शर्मा को साहिबाबाद से प्रत्याशी बनाया गया।

इस सीट पर वैश्य वर्ग के अतुल गर्ग को चुनाव लड़ाया गया, वह बसपा के सुरेश बंसल से हारे। 2017, 2022 के उपचुनाव में उनको दोबारा मौका मिला तो उन्होंने लगातार दो बार जीत हासिल की।

संजीव शर्मा का प्रोफाइल 2007 में भाजपा में शामिल हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष बने 2013 में उनको भाजपा ने महानगर महामंत्री बनाया। 2019 में वह भाजपा के महानगर अध्यक्ष बने तीन साल का कार्यकाल खत्म होने पर दोबारा महानगर अध्यक्ष बने।

पुलिस महानिदेशक ने तीन ई-लाइब्रेरी का किया उद्घाटन

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम। पुलिस कर्मचारियों और उनके बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पुलिस लाइंस गुरुग्राम, मानेसर व भोंडसी में ई-लाइब्रेरियां स्थापित की गई हैं। शनिवार को पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने तीनों लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया।

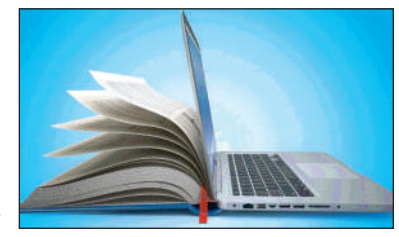

पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के अनुसार, कमिश्नरेट की पुलिस लाइंस में स्थापित की गई इन लाइब्रेरियों में विदेशी भाषा सीखने के लिए विदेशी भाषा लर्निंग केंद्र भी स्थापित किया गया है। इसमें अत्याधुनिक फर्नीचर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कंप्यूटर, किंडल और स्मार्ट बोर्ड के साथ साइबर युग में ई-बुक्स की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। स्पेनिश, फ्रेंच, जापानी एवं अंग्रेजी भाषा सीखने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए लर्निंग केंद्र में ऑनलाइन प्रशिक्षक उपलब्ध कराया गया है। लाइब्रेरी को बिजली की असुविधा न हो, इसके लिए सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है।

एक साथ 100 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था

आधुनिक एवं आदर्श पुस्तकालय के स्वरूप को साकार करते हुए कंप्यूटर सिस्टम के साथ एलईडी स्क्रीन एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक पुस्तकालयों में एक समय में 100 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था है। हरियाणा पुलिस की ओर से अब तक विभिन्न जिलों में 18 पुलिस लाइंस में पुस्तकालय का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष सात पुलिस परिसरों में पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस द्वारा स्थापित इन पुस्तकालयों से पढ़कर काफी संख्या में बच्चों ने रोजगार प्राप्त किया है। भविष्य में भी ये आधुनिक पुस्तकालय बच्चों की सफलता में अहम भूमिका अदा करते रहेंगे।

यह पुस्तकें है मौजूद

इन नवनिर्मित पुस्तकालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए पुस्तकों सहित गीता प्रेस, नेशनल बुक ट्रस्ट का संपूर्ण सेट, साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित किताबें जिसमें भारतीय भाषाओं के क्लासिकल साहित्य, प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित हिन्दी व अंग्रेजी का समस्त सेट, भगवद्गीता, पंडित लखमीचंद समग्र, पंडित लखमीचंद रचनावली, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की ग्रंथावली के साथ महात्मा गांधी, विवेकानन्द समग्र, पंडित दीन दयाल उपाध्याय की रत्नावली, अटल बिहारी वाजपेयी की श्रेष्ठ कविताएं जैसी किताबें भी उपलब्ध हैं। रूपा और पेंगुईन द्वारा प्रकाशित विश्व क्लासिक साहित्य का संपूर्ण सेट भी पुस्तकालय में उपलब्ध है।

साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुस्तैद

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी के लगातार बढ़ रहे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने कमर कस ली है। धोखाधड़ी होने पर 6 घंटे के भीतर पुलिस को सूचना मिलने पर साइबर धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसी जा सकती है और पीड़ित का 70 प्रतिशत तक पैसा रिकवर किया जा सकता है। धोखाधड़ी होने पर 1930 पर सूचना दें। पुलिस लाइंस में पुस्तकालय का उद्घाटन करने के बाद पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर पुलिस महानिदेशक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी डीसीपी व एसीपी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की।

सिविल डिफेंस के बीस आपदा मित्रों को दिया लखनऊ में एसडीआरएफ ने प्रशिक्षण

मथुरा। मथुरा जनपद से गए 105 स्वयंसेवकों को एसडीआरएफ द्वारा लखनऊ में संकटकालीन स्थिति से निपटने के तौर तरीकों से अवगत कराया। अब मथुरा में किसी भी संकटकालीन एवं प्राकृतिक आपदा के दौरान राज्य आपदा मोचन दल के साथ सिविल डिफेंस होमगार्ड के 105 प्रशिक्षित स्वयंसेवक पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे। इन्हें संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए लाइफ जैकेट के अलावा अन्य उपकरण भी उपलब्ध कराए गए है और उन्हें प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ताकि यह उसका उपयोग कर सकें। इस प्रशिक्षण के दौरान मेजर सरवन कुमार यादव प्रशिक्षण कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र दुबे ने प्रोजेक्टर के माध्यम से डिस्प्ले की और प्रशिक्षण से संबंधित कई पहलुओं को भी दिखाया। समापन मौके पर एसडीआरएफ के सेनानायक डॉ. सतीश कुमार, उप सेनानायक शुएब इकबाल, वरिष्ठ सहायक सेनानायक आत्म प्रकाश यादव, सहायक सेनानायक (प्रशिक्षण प्रभारी) सोभनाथ यादव सैन्य सहायक एहसान उल्लाह खान शिविर पाल बीएन गुप्ता सूबेदार सैन्य सहायक राज शेखर श्रीवास्तव एमटी प्रभारी राजेश कुमार शुक्ला अजय चाहर अजय बघेल अमित कुमार राजेश कुमार मनोज कुमार, प्रशांत आदेश रामबाबू इन सभी प्रशिक्षण से संबंधित कई पहलुओं पर सभी जिलों से आए आपदा मित्र मथुरा जौनपुर मिर्जापुर कौशांबी अयोध्या के सभी जिलों के 359 आपदा मित्र को 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया था। ट्रेनिंग में मथुरा सिविल डिफेंस से एनडीआरएफ एकेडमी नागपुर से प्रशिक्षित वार्डन अशोक यादव के द्वारा कमान संभाली गई। इस मौके पर सेक्टर वार्डन राम सैनी शुभम्कुमार निवेश्वरी गुलशेर राजेश कुमार देवेन्द्र कुमार पवन प्रकाश यतेंद्र पवन शर्मा मुकेश शर्मा गोविन्द चरन सिंह जीतेश राजेंद्र पंकज गर्ग नरेश अग्रवाल सोहन लाल आदि आपदा मित्रों ने प्रशिक्षण में भाग लिया था। सिविल डिफेंस मथुरा के उप नियंत्रक जसवंत सिंह सहायक उप नियंत्रक जितेन्द्र देव सिंह चीफ वार्डन राजीव अग्रवाल डिप्टी चीफ वार्डन कल्याण दास अग्रवाल सीनियर स्टॉफ ऑफिसर दीपक चतुर्वेदी बैंकर, डिवीजनल वार्डन भारत भूषण तिवारी डिप्टी डिवीजनल वार्डन राजेश कुमार मित्तल आदि ने गहन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सिविल डिफेंस वार्डन की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मथुरा में आपातकालीन स्थिति में सिविल डिफेंस अब पुलिस प्रशासन के साथ अहम भूमिका अदा करेंगी।

गाजियाबाद के नए विधायक संजीव शर्मा का बड़ा एलान, कहा- दो साल में करूंगा पांच साल के बराबर विकास

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद उपचुनाव में बीजेपी के संजीव शर्मा ने जीत हासिल की है। सपा के सिंह राज जाटव पर जीत के बाद नए विधायक संजीव शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दो साल के कार्यकाल में पांच साल जितना विकास कराऊंगा। दूधेश्वरनाथ मंदिर कॉरिडोर बनवाने के साथ ही चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पर काम करूंगा।

गुरुग्राम। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में उपचुनाव के बाद विधायक चुने गए संजीव शर्मा का बतौर विधायक कार्यकाल लगभग दो साल का होगा। उनका कहना है कि दो साल के अंदर ही पांच साल जितना विकास कार्य कराऊंगा। इनमें दूधेश्वरनाथ मंदिर कॉरिडोर बनवाने के साथ ही चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पर कार्य कराऊंगा। यह बातें दैनिक जागरण से बातचीत के दौरान नवनिर्वाचित विधायक संजीव शर्मा ने कही।

उन्होंने बताया कि शहर में जाम की समस्या को दूर कराने का प्रयास करेंगे। लाइनपार क्षेत्र में जलनिकासी का मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। नालों और नालियों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। जिससे कि वर्षा के दौरान लोगों को जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़े। पेयजल की समस्या को दूर कराने के लिए गंगाजल उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। गाजियाबाद में एम्स का सेटेलाइट सेंटर बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, उसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो। इसके लिए प्रयास करेंगे।

महामाया स्टेडियम में होगा खेल सुविधाओं का विकास

उन्होंने कहा कि महामाया स्टेडियम में खेल की सुविधाओं को और बेहतर कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि खिलाड़ियों को परेशानी न हो। उपचुनाव में एकतरफा भारी मतों से जीत पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर लोगों को भरोसा है,

इसी वजह से मतदाताओं ने एकतरफा भाजपा के पक्ष में मतदान किया है।

सपा के सिंह राज जाटव को हराया

बता दें, संजीव शर्मा गाजियाबाद के नए विधायक बन गए है। उन्होंने उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंह राज जाटव को 69 हजार से अधिक मतों से हराया। 25वें राउंड की गिनती के बाद संजीव शर्मा को 96,878 मत मिले, जबकि सपा प्रत्याशी को 27174 मत मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के प्रत्याशी पीएन गर्ग रहे, जिन्हें 10729 मत हासिल हुए।

विश्व में भारत की साख बढ़ाने की मोदी प्रतिबद्धता

ललित गर्ग

अब तक विदेशों में कुल 19 बार प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें महाशक्ति कहे जाने वाले देश रूस और अमेरिका के अलावा मालदीव, फिलीस्तीन, इजिप्ट, बहरीन और युएई जैसे मुस्लिम राष्ट्र भी शामिल हैं।

दुनिया में भारत एवं भारतीय लोकतंत्र का गौरव एवं सम्मान दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विश्व नेता बनकर उभरे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका रुतबा लगातार बढ़ा है। विदेशी धरती से मिलने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की एक लम्बी श्रृंखला इस बात का प्रमाण हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि वैश्विक स्तर पर सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित हुई है और उनकी सोच, नीतियों एवं कार्यक्रमों को विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है। यह भारत के लिये गर्व की बात है। इसी श्रृंखला में अपनी तीन देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका और गुयाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में ब्राजील में जी 20 समिट की बैठक के लिए पहुंचे थे और इसके बाद 3 कैरेबियन देशों की यात्रा पर है। कोरोना काल में मानवीय दृष्टि से मदद का हाथ बढ़ाने के लिए डोमिनिका ने प्रधानमंत्री मोदी को 'डोमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर' और गुयाना ने 'ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस' से नवाजा।

भारत के लिये सौभाग्य की बात है कि नरेन्द्र मोदी जैसा महानायक प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। वैसे तो दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है लेकिन इसी सप्ताह उनकी डोमिनिका, गुयाना और नाइजीरिया यात्रा के दौरान उन्हें जो सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, वह हर भारतीय को अभिभूत एवं गौरवान्वित कर देने वाले हैं। ये सम्मान उनके व्यापक सोच, मानवीय दृष्टिकोण, कुशल राजनीतिक नेतृत्व और दूरदृष्टि का प्रतिबिम्ब है जिसने वैश्विक मंच पर भारत के उदय एवं उसकी साख को मजबूत किया है। ये सम्मान दुनिया भर के देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कुशलता, परिपक्वता एवं दूरदर्शिता से देश का समग्र विकास करते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर किया, इससे पूरा देश तो आत्मविश्वास से भर ही उठा बल्कि पूरी दुनिया में भारत को लेकर सकारात्मकता, उम्मीदें और भरोसा बढ़ा है।

अब तक विदेशों में कुल 19 बार प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें महाशक्ति कहे जाने वाले देश रूस और अमेरिका के अलावा मालदीव, फिलीस्तीन, इजिप्ट, बहरीन और युएई जैसे मुस्लिम राष्ट्र भी शामिल हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा बार विदेशी संसद को संबोधित करने का रिकॉर्ड भी मोदी के नाम ही है। मोदी आश्चर्यों की वर्णमाला से गूंथित ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपने हर कीर्तिमान से भारत का मस्तक ऊंचा किया है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर चुके हैं। मोदी ने 14 बार विदेशी संसद में वहां के सांसदों को संबोधित किया। अमेरिका में मोदी ने दो बार संसद को संबोधित किया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फिजी, मॉरिशस, युगांडा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मंगोलिया, अफगानिस्तान और मालदीव की संसद को भी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने 7 बार, इंदिरा गांधी ने 4 बार, जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार, जबकि मोरारजी देसाई और पीवी नरसिम्हा राव ने 1-1 बार विदेशी संसदों में संबोधन दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे तो सारे शासकीय प्रोटोकाल को तोड़ कर उस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने न केवल मोदी का स्वागत किया साथ ही एयरपोर्ट पर सबके सामने मोदी के पांव भी छूए। यह अपने आप में अभूतपूर्व है कि विश्व के इतिहास में आज तक कभी भी किसी राष्ट्राध्यक्ष ने किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के पांव सार्वजनिक रूप से नहीं छूए हो।

भारत की जनता ने महानायक मोदी को एक नए भारत के शिल्पकार के रूप में देखा। मोदी की हर देश की यात्रा ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय बनी है। बात चाहे अमेरिका यात्रा की हो, वहां राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी गले तो मिले ही साथ ही बाइडेन का यह कहना अपने आप में अद्भुत है कि ''आप तो अद्भुत लोकप्रिय हो। मुझे तो आपके आटोग्राफ लेने चाहिए।'' आस्ट्रेलिया के सिडनी में जिस तरह से पूरा स्टेडियम वहां बसे भारतीयों ने ठसाठस भर दिया और पूरा स्टेडियम मोदी-मोदी के नारों से गुंजायमान हो उठा। उसे देखकर तो आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीस भी हैरान रह गए। दुनिया के बडे.नेता जहां मोदी को सर आंखों पर बैठा रहे हैं, वहीं भारत में मोदी की लगातार बढ़ती साख एवं सम्मान से समूचा विपक्ष बौखलाया हुआ है। मोदी का जितना विरोध किया जा रहा है, उतनी ही उनकी प्रतिष्ठा एवं जनस्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। एक तरह से विरोध उनके लिये वरदान बन रहा है। इस युगनायक पर कीचड़ उछालने की जिस तरह की हरकतें की गई, वर्तमान में वे पराकाष्ठा तक पहुंच गयी है। पर इससे मोदी का वर्चस्व धूमिल होने वाला नहीं है। क्योंकि उनकी राजनीति एवं नीति विशुद्ध है और सैद्धान्तिक आधार पुष्ट है।

आज भारत देश की वैश्विक साख और गरिमा में जो वृद्धि हुई है उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। विश्व शांति की स्थापना में भारत का योगदान हो या प्रौद्योगिकी के विशाल क्षितिज में लंबी उड़ान, यह सब प्रधानमंत्री की विशाल दृष्टि से संभव हो रहा है। हम सब बदलाव की इस प्रक्रिया को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह सौभाग्य से कम नहीं है। मोदी का संपूर्ण व्यक्तित्व एक पाठशाला बन गया है। उनके व्यक्तित्व के कई अनूठे आयाम हम देख चुके हैं, जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। उनकी सबसे बड़ी और असाधारण बात है उनके वक्तव्य और भाषण। जितनी स्पष्टता और प्रभावी तरीके से वे अपनी बात रखते हैं वह विलक्षण है। उनकी दूरदृष्टि या विजन बिल्कुल स्पष्ट होता है। उन्होंने लोगों में विश्वास जगाया है कि भारत में आर्थिक विकास करने और दुनिया में अपना प्रभुत्व कायम करने की क्षमता है। कठोर परिश्रम एवं अनुशासित जीवन के प्रति उनके अनुराग ने दुनिया को प्रभावित और प्रेरित किया है। राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ में एक बाल स्वयं सेवक बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक उनका जीवन अनुशासित रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए, हर पल उत्साह से बिताना और नियमित योग करना उनकी दिनचर्या है। कई अवसर ऐसे आये जब श्री मोदी ने यह सिखाया और प्रयोग करके दिखाया कि कैसे धैर्य और विनम्रता सबसे भरोसेमंद साथी है। इनके सहारे कठिन चुनौतियों से निपटा जा सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी में समय के साथ चलने और समय के पार देखने की अद्भुत क्षमता है। इसीलिए उन्होंने अपने नेतृत्व में जितनी योजनाएं बनाई वे सब वर्तमान को मजबूत बनाते हुए भविष्य को सुरक्षित करने वाली योजनाएं हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत समृद्ध भारत का मिशन पूरा करने और भारत को विश्व की प्रथम 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के महान लक्ष्य को पूरा करते हुए भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरते हुए विश्व नेतृत्व की क्षमताओं को उजागर कर रहा है। मोदी की सभी योजनाओं का उद्देश्य देश को विकसित बनाना और आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारना है। नागरिकों को अच्छी सुविधाएं, आत्मनिर्भर जीवनयापन के अच्छे विकल्प, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छा रोजगार, बेहतर वातावरण आदि उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्किल इंडिया मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अमृत योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आत्मनिर्भर भारत ने वर्तमान भारत की तस्वीर बदल दी है। भारतीय लोकतंत्र में एक स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ है और उसमें निरंतर नये-नये आयाम जुड़ते जा रहे हैं जिसे समूची दुनिया आश्चर्य से देख रही है। 'सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र अब हर नागरिक का सूत्र वाक्य है। मोदी के नेतृत्व में कई परिवर्तनकारी पहल की गई हैं, जिनका भारत पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। उनके 'स्वच्छ भारत' अभियान ने पूरे देश में स्वच्छता और सफाई के बारे में जागरूकता बढ़ाई है, जबकि 'मेक इन इंडिया' पहल का लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है। इसके अतिरिक्त, मोदी के 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम ने देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में काफी सुधार किया है, जिससे प्रौद्योगिकी सभी के लिए अधिक सुलभ हो गई है। दस वर्ष का कुशल देश संचालन, विकास की नयी इबारत लिखना, विश्वमंचों पर भारत की साख को बढ़ाना आदि घटनाओं के साक्षी रहे लोगों का अनुभव है कि इस अवधि में जितना एवं जैसा भारत बना है, उसमें विश्व को नयी दिशा देने की क्षमता है। भारत की जनता उन्हें एक नए भारत के अभ्युदय के आधारस्तंभ के रूप में देख रही है।

– :सौजन्य :–

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

EV Drive the Future

अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रा नई सहायक कंपनी के साथ ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रवेश के साथ करेगी विस्तार

परिवहन विशेष न्यूज

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक नई सब्सिडियरी के गठन की घोषणा की। इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि अब वह हर तरह के वाहनों और परिवहन के लिए हर तरह के ईंधन का इस्तेमाल करने वाले कलपुर्जों का निर्माण और बिक्री करना चाहती है।

सितंबर की शुरुआत में यह बात सामने आई थी कि अंबानी की अगुआई वाली यह कंपनी इलेक्ट्रिक कार और बैटरी बनाने की योजना बना रही है। इसके अलावा, नई एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रिलायंस ग्रुप की इस कंपनी ने चीन की बीवाईडी कंपनी के एक पूर्व भारतीय कार्यकारी को योजना तैयार करने के लिए नियुक्त किया है।

अंबानी के नेतृत्व वाली बीएसई स्मॉलकैप पावर यूटिलिटी कंपनी ने बुधवार को कंपनी की सहायक कंपनी रिलायंस वेलोसिटी लिमिटेड द्वारा एक नई सहायक कंपनी के गठन की घोषणा की, जिसे रिलायंस क्लीन ईवी प्राइवेट लिमिटेड (आरसीईवीपीएल) कहा जाएगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, ₹आरसीईवीपीएल को 20 नवंबर, 2024 को रिलायंस वेलोसिटी लिमिटेड (आरवीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 20 नवंबर, 2024 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

अंबानी की अगुआई वाली कंपनी ने बताया कि नवगठित सहायक कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी 1,00,000 रुपये है, जिसमें 10 रुपये प्रति शेयर के 10,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। रिलायंस क्लीन ईवी प्राइवेट लिमिटेड ने अभी परिचालन शुरू नहीं किया है।

इस बीच, रिलायंस समूह की कंपनी

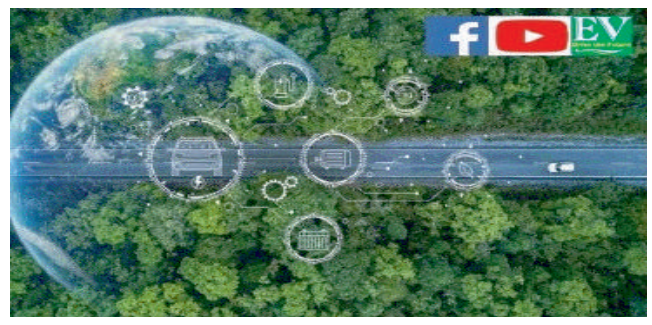

इलेक्ट्रिक कारों और बैटरियों के निर्माण की योजना पर विचार कर रही है, रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने ईवी संयंत्र स्थापित करने के लिए ₹लागत व्यवहार्यता₹ अध्ययन करने के लिए बाहरी सलाहकारों को काम पर रखा है, जिसकी प्रारंभिक क्षमता लगभग 250,000 वाहन प्रति वर्ष होगी, जिसे कुछ वर्षों में 750,000 तक बढ़ाया जाएगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कंपनी ने पिछले महीने भारत में सबसे बड़ा एकीकृत रक्षा विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की योजना का अनावरण किया था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अपनी सहायक कंपनी रिलायंस डिफेंस के माध्यम से इस ग्रीनफील्ड परियोजना को विकसित करने के लिए अगले दशक में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जो नागरिक और सैन्य दोनों अनुप्रयोगों के लिए विस्फोटक, गोला-बारूद और छोटे हथियारों के निर्माण पर केंद्रित होगी।

मोबिलिटी का भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों में ही है, उद्योग जगत के लीडर्स ने कहा

परिवहन विशेष न्यूज

शिखर सम्मेलन के दौरान मर्सिडीज-बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ संतोष अय्यर, बॉश एसडीएस के सीईओ देबाशीष बिसोई, टाटा मोटर्स के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर शुभ्रांशु सिंह और पोर्शे कंसल्टिंग के सीनियर पार्टनर हेगन रोडोवस्की ने फ्यूचर ऑफ मोबिलिटीः को-ड्राइविंग द एजेंडा सत्र में हिस्सा लिया।

इस चर्चा के दौरान शुभ्रांशु सिंह ने कहा कि जिस तरह से तकनीक और उद्योग आगे बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार निकट भविष्य में मोबिलिटी का भविष्य इलेक्ट्रिक ही है। इसको लेकर एक इकोसिस्टम बनने लगा है। वहीं मर्सिडीज बेंज के संतोष अय्यर ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अभी भविष्य इलेक्ट्रिक का है, हालांकि भविष्य क्या होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

शुभांशु का कहना है कि टाटा मोटर्स भारत में इस क्षेत्र में पहले से ही मार्केट लीडर है। जबकि भारत ने फ्लीट, डिलीवरी, लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर अच्छा ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने इससे जुड़ी चुनौती का भी जिक्र किया कि लोगों को इसे तेजी से अपनाने में समय लगेगा।

उन्होंने कहा कि अब इलेक्ट्रिक मोटर को लेकर ग्राहकों का भरोसा बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि पर्यावरण को बेहतर बनाने में उनका भी कुछ योगदान है।

क्या ए.आई. आने वाले समय में ड्राइवरलेस कार को हकीकत बना देगा? इस सवाल का जवाब हेगन रोडोवस्की ने दिया। उन्होंने कहा कि यह काफी हद तक संभव है। लेकिन अभी कंपनियां इससे सिर्फ इसलिए बचती हैं, क्योंकि दुनियाभर की सड़कों पर मिक्स ट्रैफिक देखने को मिलता है। वाहनों की लागत कम करने के मामले पर देवाशीष बिसोई ने कहा कि लागत कम करने के कई पहलू हैं। इसमें सुरक्षा, समय और तकनीक की अहम भूमिका होती है। ऐसे में इनमें से किसी एक कारक को कम करके लागत कम नहीं की जा सकती।

समिट के दौरान यूनिकॉर्न टुडे, एम.एन.सी. टुमॉरो विषय पर टी.सी.जी. के चेयरमैन पुरेंदु चटर्जी ने कहा कि अगर स्टार्टअप को आगे बढ़ना है, तो उन्हें यह देखना होगा कि भविष्य का कारोबार कहां है। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी शेयर बाजार के पूंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि का जिक्र किया। इतना ही नहीं, भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यहां शोध और विकास पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि आज आधार और यूपीआई के अलावा ऐसा कोई भारतीय उत्पाद नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए उपयुक्त हो। इसलिए भारत में स्टार्टअप्स को शोध पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी हम सोडियम आयन बैटरी के बिल्कुल शुरुआती बिंदु पर हैं। ऐसे में भारतीय कंपनियां भविष्य के लिए यहां बड़ा योगदान दे सकती हैं।

विशेषज्ञों ने फास्ट-चार्जिंग के साथ ईवी अपनाने में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक-निजी निवेश को बढ़ावा देने का किया आह्वान

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में 4 मिलियन से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बिक चुके हैं, इसलिए देश में ईवी अपनाने की प्रवृत्ति तेज़ी से बढ़ रही है। हालाँकि, विशेषज्ञ इस बदलाव को तेज़ करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के निवेश का आग्रह कर रहे हैं। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस ने नई दिल्ली में इंडिया ईवी फ़ास्ट चार्जिंग समिट की मेज़बानी की, जहाँ उद्योग जगत के नेताओं ने प्रतीक्षा समय को कम करने और ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए गतिशीलता बढ़ाने के लिए फ़ास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के महत्व पर प्रकाश डाला।

आईईएसए के अध्यक्ष देबी प्रसाद दाश ने आगामी पीएम ई-ड्राइव योजना पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह योजना स्थानीय वाहन घनत्व पर विचार करेगी और पहुंच में सुधार के लिए राज्यवार आवंटन की पेशकश करेगी।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि पूरे

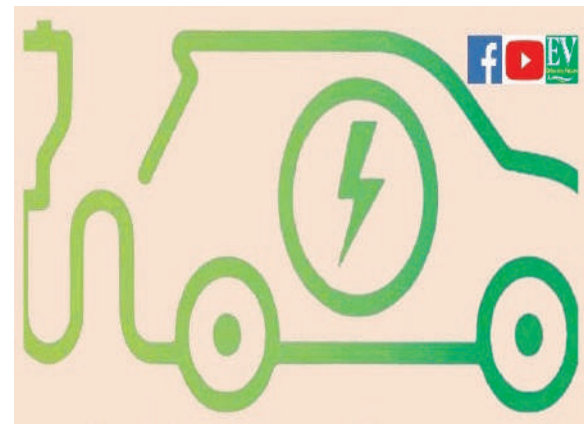

भारत में चार्जिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 50 बिलियन डॉलर तक के निवेश की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने ईवी घटकों पर सीमा शुल्क जैसी लागतों को कम करने और विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय अनुसंधान और विकास को समर्थन देने का भी आह्वान किया।

ग्लिडा के कार्यकारी निदेशक अवधेश झा ने बताया कि फास्ट चार्जर्स को समर्थन देने के लिए बिजली के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए अधिक धनराशि खर्च की जानी चाहिए। एक्सिकॉम के सीएफओ शिराज खन्ना ने भी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के महत्व पर जोर दिया।

2030 तक 30 प्रतिशत ईवी अपनाने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, सरकार और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को मजबूत करना एक स्थायी ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की कुंजी है।

भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 20-30 बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने की प्रक्रिया तेजी से अपने चरम पर पहुंच रही है, जिसका श्रेय अनुकूल माहौल, सरकारी नीतियों का समर्थन और उपभोक्ताओं में बढ़ती जागरूकता को जाता है। हालांकि, सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से अपनाने की दर में तेजी लानी होगी। उद्योग समूह आईईएसए ने चार्जिंग समय को कम करने और ईवी उपभोक्ताओं के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में इंडिया ईवी फास्ट चार्जिंग समिट का आयोजन किया। भारत में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दर को दोगुना करने के लिए 20-30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।

उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि 2030 तक 30 प्रतिशत ईवी अपनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मूल्य अंतर को कम करेंगे और ईवी को अधिक किफायती बनाएंगे। आयातित ईवी घटकों पर सीमा शुल्क, जीएसटी और करों को कम करना, साथ ही घरेलू आरएंडडी बैटरी प्रौद्योगिकी के लिए अभियान चलाना, स्थानीय विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। डिस्कॉम (वितरण फर्म) ईवी अपनाने को बढ़ावा देने और अंतिम उपयोगकर्ताओं को भरोसेमंद बिजली प्रदान करके ऊर्जा उद्योग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, इस क्षेत्र में उच्च स्थापना लागत एक मुद्दा बनी हुई है। इस अंतर को पाटने के लिए निवेश की आवश्यकता है, साथ ही परियोजनाओं के लिए सरकारी समर्थन की भी आवश्यकता है।

एक्सिकॉम के सीएफओ शिराज खन्ना के अनुसार, ईवी का विस्तार केवल महानगरीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यदि बुनियादी ढांचे, ट्रांसफार्मर और

ग्रिड का आधुनिकीकरण किया जाता है, तो यह ग्रामीण क्षेत्रों तक भी फैलेगा। अंत में, भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की गति सार्वजनिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों के बीच सहयोग पर निर्भर करती है ताकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो और कीमतें कम हों। अब 4 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर हैं, ऐसे में कुशल और आसानी से सुलभ रैपिड चार्जिंग स्टेशनों की बहुत आवश्यकता है। पीएम ई-ड्राइव योजना जैसे प्रमुख प्रयास इस मांग को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक अधिक रणनीतिक निवेश रणनीति की इच्छा है जो वर्तमान बिजली प्रणाली के आधुनिकीकरण पर केंद्रित हो।

2025 रिनॉल्ट डस्टर पहली बार लोगों के सामने हुई पेश, ग्लोबल लेवल पर मार्च 2025 में होगी लॉन्च

कार निर्माता कंपनी रेनो ने 2025 Renault Duster को दक्षिण अफ्रीका में एक इवेंट के दौरान पेश किया है। कंपनी ने नई डस्टर को पहली बार लोगों के सामने पेश किया है। नई डस्टर का डिजाइन नई डासिया से बहुत ही ज्यादा मिलता-जुलता है। इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.2-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड और 1.6-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन मिल सकता है।

नई दिल्ली। रिनॉल्ट ने अपनी अपकमिंग कार नई डस्टर को पहली बार लोगों के सामने पेश किया है। कंपनी ने नई Renault Duster को दक्षिण अफ्रीका में एक इवेंट के दौरान पेश किया है। हालांकि, कंपनी की तरफ से अभी यह कंफर्म नहीं किया गया है कि नई डस्टर को भारत में लॉन्च किया जाएगा कि नहीं। वहीं, एक बात को कंफर्म हो गई है कि कंपनी नई डस्टर लेकर आ रही है, जिसे वह पहले दक्षिण अफ्रीका में मार्च 2025 में लॉन्च करेगी। आइए जानते हैं कि यह नई Renault Duster क्या फीचर्स देखने के लिए मिले हैं।

नई जनरेशन डस्टर का डिजाइन काफी हद तक नई डासिया डस्टर से मिलता-जुलता है। इतना ही नहीं, इसका प्रपोर्शन भी डासिया के ग्लोबल मॉडल की तरह ही दिया गया है।

इसमें डासिया की जगह पर Renault का बैच फ्रंट ग्रिल पर दिया गया है। वहीं, बाकि स्टाइलिंग एलिमेंट्स जैसे हेडलैम्प्स, क्लैडिंग, साइड प्रोफाइल और टेल लैम्प्स तकरीबन सभी चीजे डासिया से बहुत ही ज्यादा मिलती-जुलती है।

नई रेनो डस्टर में RHD (राइट-हैंड ड्राइव) वर्जन का इंटीरियर लेआउट, केबिन फ़ीचर्स और टेक्नोलॉजी की तरह ही दिया गया है। इसमें अंतर केवर स्टीयरिंग वील की पोजीशन का है।

भारत में पुराने डस्टर मॉडल्स की तुलना में यह बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। हालांकि, मैटेरियल की क्वालिटी और कलर ऑप्शन्स पुराने मॉडल्स की तुलना में ज्यादा अलग नहीं है।

हीरो सर्ज S32 के डिजाइन का स्केच आया सामने, ई-रिक्शा से इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3 मिनट में होगी कन्वर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

होरो की Surge S32 कनवर्टेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में साल 2025 में कभी लॉन्च हो सकती है। हाल ही में सर्ज S32 के डिजाइन का स्केच सामने आया है। जिसमें इसके टू-व्हीलर से थ्री-व्हीलर में बदलने की जानकारी मिल रही है। साथ ही इसके बाहरी डिजाइन की भी कई जानकारी देखने के लिए मिली है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प के स्वामित्व वाली सर्ज ईवी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी जल्दी ही भारत में S32 2W-cum-3W को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इसके डिजाइन को पेटेंट भी करा लिया है। इसे कंपनी साल 2025 में कभी लॉन्च कर सकती है। हाल ही में इसके डिजाइन का स्केच सामने आया है। आइए जानते हैं कि Hero Surge S32 कन्वर्टिबल इलेक्ट्रिक स्कूटर किन फीचर्स के साथ आ सकती है।

Hero Surge S32: क्या होंगे फीचर्स

सर्ज S32 में एक हाइब्रिड वाहन है, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर गैर-स्वचालित रियर मॉड्यूल के लिए फ्रंट व्हील के रूप में काम करता है। इसमें अपना बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर भी दिया जाएगा। इसमें ऐसा इसलिए दिया जाएगा ताकि स्कूटर और गैर-स्वचालित रियर मॉड्यूल दोनों में स्वतंत्र पावरट्रेन हो।

इसे कई वेरिएंट के साथ पेश किया जाएगा। इसके थ्री-व्हीलर ऑटो रिक्शा (S32 PV), एक थ्री-व्हीलर कार्गो वाहन (S32 LD), एक थ्री-व्हीलर कवर कार्गो वाहन (S32 HD) और एक फ्लैट-बेड थ्री-व्हीलर कार्गो वाहन (S32 FB) वेरिएंट के साथ लाया जाएगा।

सर्ज S32 एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक 3W कमर्शियल वाहन को एक पैकेज में जोड़ता है। ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। जिसकी वजह से कंपनी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर L2-5 नामक एक नई वाहन श्रेणी बनाई है।

नई श्रेणी टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर कॉम्बी मॉड्यूल वाहन को रिप्रजेंट करती है, जिसमें L2 स्कूटर को नॉन सेल्फ-प्रोपेल्ड रियर मॉड्यूल के जोड़ा गया है।

Hero Surge S32: स्केच में क्या दिखा

देखने में सर्ज S32 इलेक्ट्रिक स्कूटर पार्ट युवा डिजाइन के साथ एक पारिवारिक स्कूटर जैसा दिखाई देता है। इसके नॉन सेल्फ-प्रोपेल्ड रियर मॉड्यूल का वजन सहन करने के लिए दोनों पहियों पर शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है।

इसके आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दिया गया है, जो थ्री-व्हीलर CV के लिए अद्वितीय है। इसका रियर मॉड्यूल स्कूटर पर टिका होता है और ऑपरेटर स्कूटर की सीट पर बैठ कर इसे चलाता है।

ईयू और चीन के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों पर खत्म होगा शुल्क, व्यापार तनाव के बीच नई उम्मीद

परिवहन विशेष न्यूज

चीन और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़ा समझौता होने जा रहा है। यूरोपीय संघ चीन से यूरोप में आयात किए जाने वाले चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क हटाने जा रहा है। यूरोपीय संसद की अंतरराष्ट्रीय व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्न्ड लैंग ने शुक्रवार को घोषणा की कि दोनों पक्ष बातचीत के अंतिम दौर में हैं।

बर्न्ड लैंग ने संकेत दिया कि जल्द ही दोनों पक्ष किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं, जिसके तहत चीनी ईवी पर कर माफ किया जा सकता है। इस घोषणा के बाद पश्चिमी देशों की ईवी कंपनियों की चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि चीन के ईवी उनसे काफी सस्ते हैं और शुल्क हटाने से उनकी कीमतें और कम हो जाएंगी।

बर्न्ड लैंग के अनुसार यूरोपीय संघ और चीन चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क खत्म करने के लिए लगभग तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चीन यूरोप में उचित कीमतों पर ईवी बेचने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचना चाहता है।

इस कदम से चीन द्वारा अपने इलेक्ट्रिक

वाहन उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी पर चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी। यूरोपीय संघ का दावा है कि ये सब्सिडी चीनी कंपनियों को यूरोप में कम कीमत पर ईवी बेचने में मदद करती है, जिससे यूरोपीय कार निर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में, यूरोपीय कंपनियों को इस प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए यूरोपीय संघ ने चीनी ईवी पर टैरिफ लगाया था।

अक्टूबर 2023 में यूरोपीय संघ ने चीन से आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 35.3 प्रतिशत तक का अतिरिक्त शुल्क लगाया। जब यूरोपीय संघ ने कहा कि यूरोपीय निर्माता चीनी सब्सिडी के कारण अपने वाहन नहीं बेच पा रहे हैं। यूरोपीय आयोग को डर था कि चीनी ईवी आयात में वृद्धि से यूरोपीय ऑटोमोटिव क्षेत्र में स्थानीय व्यवसायों और नौकरियों को नुकसान हो सकता है।

चीन ने भी इस फैसले को हल्के में नहीं लिया और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अब नई बातचीत में उम्मीद है कि चीन और यूरोपीय संघ के बीच संबंध बेहतर हो सकते हैं।

यूरोपीय संघ और चीन के बीच व्यापार संबंधों में एक नाजुक संतुलन है, दोनों पक्ष अपने उद्योगों की रक्षा करने के साथ-साथ एक बड़े व्यापार युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यदि यह समझौता हो जाता है, तो यह इन तनावों को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।

मिलावटी दूध से खतरे में सेहत

विजय गर्ग

देश भर में बच्चे-बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बीमार व्यक्ति प्रतिदिन दूध और इससे बने उत्पादों का सेवन करते हैं। मगर दूध में मिलावट से स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, जिनके परिणामस्वरूप घातक बीमारियां सामने आती हैं। बाजार में उपलब्ध दूध से तैयार अधिकांश उत्पादों में पानी, सिंथेटिक रसायन, यूरिया और अन्य हानिकारक तत्त्वों की मिलावट पाई गई है। इस समस्या का वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करना आवश्यक है, ताकि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर परिणामों को लेकर सचेत हुआ जा सके। यह जानना समझना महत्त्वपूर्ण है कि दूध में मिलावट के लिए कौन-कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता और ये स्वास्थ्य पर किस प्रकार असर डालते हैं।

x आमतौर पर दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिलाया जाता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए कुछ मायनों में ही हानिकारक है। असली खतरा तब पैदा होता जब इसमें यूरिया, डिटर्जेंट, सिंथेटिक दूध, स्टार्च और कुछ रसायन मिलाए जाते हैं। ये रसायन दूध के प्राकृतिक पोषण को नष्ट करते हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होते हैं। उदाहरण के लिए, यूरिया एक रासायनिक यौगिक है जिसे सामान्यतः कृषि में उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन जब इसे दूध में मिलाया जाता है, तो यह न केवल दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि गुर्दे, लीवर और अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।

दुग्ध के कुछ प्रोटीन परीक्षणों में नाइट्रोजन की मात्रा मापी जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन की उच्च मात्रा होने कारण, यूरिया मिले दूध के परीक्षणों में प्रोटीन की मात्रा कृत्रिम रूप से अधिक दिखाई देती है। यह मिलावट न केवल उपभोक्ताओं को भ्रमित करती बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की रपट के अनुसार, हर साल लगभग 60 करोड़ लोग खाद्य मिलावट के कारण बीमार पड़ते हैं, जिनमें । कई मामलों में मिलावटी दूध का सेवन शामिल है। इसी तरह, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की एक रपट में यह बताया गया कि 2018 में किए गए एक अध्ययन में 68 फीसद दूध के नमूने मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं थे प्राधिकरण ने चेतावनी दी कि मिलावट वाले दूध का सेवन करने वाले लोगों में कैंसर के मामलों में 30 फीसद वृद्धि हो सकती है। यह स्थिति विशेषः तब गंभीर हो जाती है, जब मिलावट में रासायनिक तत्त्व, जैसे फार्मेल्डहाइड और यूरिया शामिल होते हैं, जो कैंसर की वजह बनते हैं और जीन में परिवर्तन का कारण बन सकते हैं।

। फार्मेल्डेटाइड शरीर की कोशिकाओं में जीन में परिवर्तन कर कैंसर का जोखिम बढ़ा देता है, जबकि यूरिया की मिलावट दूध की गुणवत्ता को कृत्रिम रूप से बढ़ा देती है। इन रसायनों का सेवन न केवल कैंसर का खतरा पैदा करता है, बल्कि गुर्दे और लीवर की विफलता जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। अनुसंधान से यह भी स्पष्ट है कि मिलावट के कारण गुर्दे की विफलता के मामलों में चालीस फीसद और हृदय रोगों के मामलों में पच्चीस फीसद तक की वृद्धि हो सकती है। डब्लूएचओ की 'कैंसर रिस्क असेसमेंट' रपट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रासायनिक मिलावट से प्रभावित व्यक्तियों स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं।

ऐसे में, विश्वसनीय परीक्षण प्रणालियों का विकास और क्रियान्वयन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में भारत में दूध की शुद्धता जांचने के लिए कई तरीकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इनमें से कई परीक्षण तकनीक पुरानी और अप्रभावी साबित हो रही हैं। हमें अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जो दूध में मिलावट का तुरंत और सटीक पता लगाने में सक्षम हों, ताकि मिलावट की समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। उदाहरण के लिए एचपीएलसी एक अत्यंत संवेदनशील तकनीक है जो दूध यूरिया, डिटर्जेंट और सिंथेटिक पदार्थों की पहचान के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस तकनीक का उपयोग करके मिलावट का पता लगाया जा सकता है। 'जर्नल आफ डेयरी साइंस' में प्रकाशित शोध के के अनुसार, एचपीएलसी तकनीक का उपयोग करके दूध में मिलावट की पहचान करने की सटीकता सत्तानवे फीसद तक थी। गैस क्रोमेटोग्राफी (जीसी) भी एक प्रभावशाली तकनीक है, जिसका उपयोग दूध में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और अन्य रसायनों की पहचान के लिए किया जाता है। यह विधि दूध में मिलावटी तत्त्वों की पहचान के लिए अत्यधिक सटीक मानी जाती है। इन तकनीकों के उपयोग से न केवल दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे मिलावट के मामलों में भी कमी आएगी। इसलिए, के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है, ताकि दूध की शुद्धता बनी रहे और लोगों स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इन परीक्षण और प्रभावी रूप से लागू करने खाद्य इस संकट से निपटने के लिए सख्त कानून और दंडात्मक प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जाए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण सुरक्षा के कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन उनका प्रभावी पालन और नियमों का ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। बाजार में बिकने वाले अधिकांश दूध उत्पादों में मिलावट पाए जाने पर भी कई बार दोषियों पर उचित कार्रवाई नहीं होती। इससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं और मिलावट का धंधा बेरोक-टोक चलता रहता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसे दूध उत्पादकों, वितरकों और विक्रेताओं पर सख्त कानूनी सनी कार्रवाई की जाए। खाद्य मिलावट के गंभीर अपराध मान कर कर दोषियों को भारी को भारी जुमनि और कठोर कठोर कारावास का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के अपराध पर रोक लग सके। इसके अलावा, जनजागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है, ताकि उपभोक्ता स्वयं खरीदे गए दूध और जांच कर सकें और मिलावट के प्रति सजग रहें। र दुग्ध उत्पादों की तकनीकी नवाचारों के माध्यम से से उपभोक्ताओं की की जागरूकता और सतर्कता बढ़ेगी, जिससे अपनी खरीदारी में बेहतर निर्णय ले और दूध शुद्ध तथा सुरक्षित दूध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित । हो सकेगी। उत्पादकों को यह समझना चाहिए कि अल्पकालिक मुनाफे के लिए मिलावट करना समाज के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। एक शोध से यह भी प्रमाणित होता है कि मिलावट करने वाले विक्रेताओं की पहचान होने पर उनके उत्पादों की बिक्री में लगभग चालीस फीसद 5 की गिरावट देखी जाती है।

इसलिए, उपभोक्ताओं को भी शुद्धता तक सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय और स्रोतों से दूध खरीदने को प्राथमिकता देनी चाहिए। विश्वसनीय स्रोतों से दूध दूध जिससे कैंसर में मिलावट हमारे देश के स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर प्रभाव डाल रही है, कैंसर, हृदय, गुर्दे और यकृत रोगों का खतरा बढ़ रहा है। यह केवल अकेले सरकार का काम नहीं है कि वह मिलावट पर नियंत्रण करे, बल्कि दूध उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी होगी। मिलावट के खिलाफ साझे प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें सरकार, दुग्ध उद्योग और उपभोक्ता मिल कर काम करें। इसके लिए सख्त कानून, बेहतर परीक्षण प्रणालियों और नैतिक जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि भविष्य में इसके गंभीर परिणामों से बचा जा सके।

ऋतुओं को निगलने लगा प्रदूषण

विजय गर्ग

झील की कोखों से जहां झांकते थे/ धूप से सोना मढ़े भाप के छल्ले वहां अब मंडराता है घना नीला कुहरा.... 'हेमंत का गीत गाते हुए अज्ञेय ने कभी इन्हीं पंक्तियों के साथ हेमंत ऋतु का स्वागत किया था, लेकिन अब कोहरा जैसा सौंदर्य इस समय शायद ही दिखता है। खूबसूरती ही नहीं, अब तो हेमंत ऋतु भी कहां महसूस कर पाते हम ! वे दिन अब लद गए, जब सभी छह ऋतुएं हमें सुखद एहसास देती थीं। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर या शीत का एक अलग ही आनंद और उत्साह लोगों में दिखा करता था। मगर अब तो सर्दी, गरमी और बरसात, यही तीन मौसम विशेषकर उत्तर भारत के लोग अनुभव करते हैं।

ऋतुएं इसलिए खत्म हो रही हैं, क्योंकि वैश्विक गर्मी (ग्लोबल वार्मिंग) व प्रदूषण ने हमारे वातावरण को करीब-करीब बीमार बना दिया है। हेमंत की बात करें, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानसून का विस्तार होने लगा है। पहले सितंबर तक सामान्यतः मानसून खत्म हो जाता था, जिसके बाद हल्की ठंड की दस्तक होती थी। मगर इस साल अक्तूबर अंत तक मानसूनी बारिश होती रही। इसके बाद तापमान अचानक नीचे गिरा और मानो हेमंत ऋतु को उसने जैसे लील ही लिया। वैसे, इन दिनों तापमान 15-16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा, लेकिन प्रदूषण के कारण ठंड का एहसास नहीं हो सका। कुछ यही हाल वसंत का भी है। बीते तीन-चार वर्षों से मार्च-अप्रैल से ही अब हीट वेब (अत्यधिक गरमी) शुरू हो जाती है। नतीजतन, वसंत की बयार नहीं बहती, गरमी का ताप हम झेलते हैं।

दरअसल, यह अनुमान लगाया गया था कि इंसानी गतिविधियों के कारण साल 2030 तक वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होगी। मगर अभी जब तापमान 1.1 या 1.2 डिग्री सेल्सियस तक है, हम मौसम संबंधी उन तमाम मुश्किलों का सामना करने लगे हैं, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस पर तापमान के पहुंचने के बाद होने की आशंका जताई गई थी। हालांकि, अजरबैजान के बाकू में चल रहे कॉप-29 जलवायु वार्ता सम्मेलन में कहा गया है कि साल 2024 के शुरुआती नौ महीनों में वैश्विक औसत तापमान पूर्व

औद्योगिक औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इसी कारण, हम चरम मौसम की अवस्था देखने लगे हैं।

दिक्कत यह है कि इस तरह की रिपोर्ट जब आती हैं, तब तो हम सजगता दिखाते हैं, लेकिन बाद में उसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। जैसे कि साल 2017 में ही जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया था कि सर्दी में तापमान में तुलनात्मक रूप से वृद्धि देखी जा रही है, जिस कारण लोग पहले के मुकाबले कम ठंड महसूस करने लगे हैं। उसने इसकी वजह वैश्विक गर्मी बताई थी, जिसमें प्रदूषण का बड़ा योगदान होता है। मगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

असल में, सर्दियों में गंगा के मैदानी इलाकों में वातावरण काफी स्थिर हो जाता है। यह स्थिति पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देशों में भी दिखती है। इस ठहरे वातावरण में हलचल तभी होती है, जब पश्चिमी विक्षोभ जैसी कोई मौसमी परिघटना होती है। मगर ऐसा कभी-कभार ही होता है, जिस कारण यहां प्रदूषण भी ठहर जाता है। देखा जाए, तो भारत के उत्तरी हिस्से में प्रदूषण 365 दिनों की समस्या है। गर्मी में हवा गर्म हो जाने से ऊपर उठ जाती है, जिससे प्रदूषकों का बिखराव हो जाता है और वायु गुणवत्ता उतनी खराब नहीं होती। मगर सर्दियों में मौसम में ठहराव से प्रदूषण की सघनता बढ़ती जाती है। रही-सही कसर पराली और पटाखे पूरी कर देते हैं। कोहरा और प्रदूषक मिलकर स्मॉग, यानी सघन धुंध का निर्माण करते हैं, जिससे आबोहवा दम घोंटने वाली बन जाती है। कल्पना कीजिए, यदि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यूं ही महीना भर 400-500 के पार बना रहे, तो लोग किस कदर जानलेवा रोग के शिकार बन जाएंगे।

आखिर इस समस्या का समाधान क्या है ? इसका समाधान वहीं करना होगा, जहां से प्रदूषण पैदा हो रहा है। सबसे पहले, सूखे पत्तों या गोबर के उपलों का ईंधन के रूप में इस्तेमाल तत्काल बंद होना चाहिए। यह सही है कि अब गांव-गांव में घरेलू एलपीजी पहुंच चुकी है, लेकिन गैस आज भी गरीब ग्रामीणों के लिए तुलनात्मक रूप से महंगी है। इसी तरह, कूड़े को पहाड़ों को भी हमें हटाना होगा। राजधानी दिल्ली में ही कई ऐसे पहाड़ खड़े हो गए हैं, जहां से मिथेन और ओजोन जैसी हानिकारिक गैस उत्सर्जित होती रहती हैं। इनको हटाने साथ-साथ हमें सभी कॉलोनियों और सोसायटियों में स्थानीय तौर पर कचरा के निस्तारण के लिए कैप्टिव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कैप्टिव वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी लगाने होंगे, ताकि घरों का कचरा आसपास ही निस्तारित हो सके।

गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को भी हमें रोकना होगा। सार्वजनिक परिवहन पर तो हमारे देश में काम हुआ है, लेकिन अब वक्त निजी परिवहन में सुधार का है। इसके लिए सड़कों पर से डीजल वाहन ह आवश्यक हैं। परिवहन से होने वाले प्रदूषण में बड़ा योगदान डीजल वाली गाड़ियों का ही है और शहरों में ऐसी गाड़ियां बहुतायत में दिखती हैं। कार पुलिंग भी की जा सकती है। इन सबसे परिवहन प्रदूषण तकरीबन 30 फीसदी हिस्सा हम कम कर सकेंगे। जरूरी यह भी है कि सर्दियों में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश आदि हिस्सों में स्थापित कोयले से बिजली पैदा करने वाली इकाइयों को बंद किया जाए। ऐसा कम से कम 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया जाना आवश्यक है। इससे हमारी बिजली आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय बिजली की मांग काफी कम हो जाती है, जिसकी पूर्ति नजदीकी इकाइयों से की जा सकती है। इससे भी हम दिल्ली की आबोहवा में बाहर से आने वाले प्रदूषण का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा कम कर सकते हैं। फिर, पराली व पटाखों पर काम चल ही रहा है। यानी, हम प्रदूषण को काफी हद तक थाम सकेंगे। बड़ा सवाल यही है कि ऐसा होगा कैसे ? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) बनाया तो गया, पर जब तक राज्य सहयोग नहीं करेंगे, तब तक यह आयोग भी कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति भी तो इन्हीं सब बातों पर है।

गाँवों, शहरों और कस्बों में पुस्तकालयों का होना बहुत जरूरी है

विजय गर्ग

लेकिन पिछले कुछ दशकों में तकनीकी क्रांति और लोगों के बदलते रुझान के कारण किताबों और पुस्तकालयों का महत्व कम होता जा रहा है।

ज्ञान और मनोरंजन के अनंत अन्य साधनों के आगमन के साथ, लोगों ने प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया है। यह अक्सर देखा जाता है कि पुस्तकालय एक समय सबसे व्यस्त स्थान थे जहाँ लोग घंटों तक बैठ सकते थे। विभिन्न विषयों पर अध्ययन करते थे। लेकिन आजकल ये चलन पूरी तरह से बदल गया है. यहां तक कि स्कूल-कॉलेज के पुस्तकालयों में भी अब उतनी रौनक नहीं रही, जितनी पहले हुआ करती थी। छात्र लाइब्रेरी में बैठकर भी अपने मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं। वे किसी किताब, विषय या लेख के बारे में सोचने के बजाय अपने मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। घर में जो चीजें टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि में बिताई जाती हैं, वही गुण नए बच्चों में फिर से आ रहे हैं। तकनीक का इस्तेमाल न केवल हमेशा गलत उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बल्कि इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल आदि जहां मनोरंजन का साधन है, वहीं ज्ञान का भी स्रोत हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि इसके कई फायदे हैं और हर इंसान को इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा फायदा, उतना ज्यादा नुकसान. आजकल तकनीकी साधनों के बिना रहना बहुत मुश्किल है, इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी सेकंडों में उपलब्ध है जिससे समय की काफी बचत होती है और कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सूचना और ज्ञान में

अंतर होता है, सूचना तो किसी चीज को पढ़कर तुरंत प्राप्त की जा सकती है लेकिन ज्ञान अध्ययन का परिणाम है जिसे निरंतर सावधानीपूर्वक अध्ययन से ही प्राप्त किया जा सकता है। मेरा कहना यह है कि हम चाहे कितनी भी प्रगति कर लें, किताबों के प्रति हमारा प्रेम कभी नहीं टूटना चाहिए क्योंकि दुनिया में अनगिनत आविष्कार हुए हैं, लेकिन किताबें सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं और हमेशा रहनी चाहिए।

गाँवों, शहरों, कस्बों में पुस्तकालयों का होना बहुत जरूरी है जहाँ हर विषय पर अधिक से अधिक पुस्तकें हों। युवा पीढ़ी और बच्चों को पुस्तकालय में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम सभी को खुद को, अपने बच्चों और अपने आस-पास के लोगों को जितना संभव हो सके पढ़ने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र तरीका है जो हमेशा हमारे जीवन को रोशन करेगी, "उन्होंने कहा। ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसे कभी कोई लूट नहीं सकता।

किताबों से जुड़ना बहुत जरूरी है वरना हम जड़ों से दूर हो जाएंगे और जड़ों के बिना पेड़ की क्या हालत होती है ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए किताबें साझा करते रहें, अपने से जुड़े लोगों को किसी न किसी मौके पर अच्छी किताबें पढ़ने के लिए देते रहें, अगर इस तरह का लेन-देन शुरू हो जाए तो हर कोई बुद्धिमान और विवेकशील हो सकता है जिससे हमारे जीवन की मुश्किलें आसान हो सकती हैं। आइए हम सब मिलकर पुस्तक को कक्षा में पाठ्यक्रम के रूप में न पढ़कर उसके अस्तित्व को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करें और स्वयं पुस्तक के अस्तित्व को बचाएं।

प्रदेश में सडक़ों का सुधार एवं विस्तार

विजय गर्ग

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, जहां सडक़ें ही परिवहन का प्रमुख माध्यम हैं। सडक़ें न केवल यातायात के लिए आवश्यक हैं, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति में भी अहम भूमिका निभाती हैं। जलमार्ग और रेलवे जैसी सुविधाओं के अभाव में, सडक़ें हिमाचल के सामाजिक और आर्थिक ढांचे की रीढ़ के समान हैं। इन सडक़ों पर भारी वाहनों के साथ-साथ निजी वाहन भी चलते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ते यातायात के कारण, विशेषकर शहरों और कस्बों के पास, ट्रैफिक जाम और यातायात बाधित होने की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्यों के चलते संपर्क सडक़ों की स्थिति खराब हो रही है। अतः इन सडक़ों की समय पर मरम्मत और उचित रखरखाव पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। इन कार्यों को प्रभावी रूप से अंजाम देने के लिए मजदूरों और तकनीकी कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करनी चाहिए। सडक़ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सडक़ पर चिह्न (सडक़ चिन्ह) और सुरक्षा उपायों को लागू करना आवश्यक है। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए दुर्घटनाग्रस्त स्थानों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नई सडक़ों के निर्माण में भारी वाहनों की आवाजाही, जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सडक़ नेटवर्क के सुधार के लिए लगभग तीन हजार किलोमीटर सडक़ों के उन्नयन हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की है।

इससे राज्य को कई लाभ होंगे। इसके कार्यान्वयन में ठेकेदारों को उच्च गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्थानीय मजदूरों और तकनीकी विशेषज्ञों को भी इन कार्यों में शामिल करना आवश्यक है ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार हो सके। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के तहत हिमाचल प्रदेश में 3500 किलोमीटर नई सडक़ें बनाने की मंजूरी दी है। इन नई सडक़ों के निर्माण से प्रदेश के लगभग 300 गांव सडक़ सुविधा से जुड़ सकेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार, 100 से 300 की आबादी वाले गांवों को इस योजना के तहत सडक़ों की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के पहले चरण में बनीं 800 किलोमीटर सडक़ों को पक्का करने की भी मंजूरी दी है। पीएमजीएसवाई के चौथे चरण को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैठक में प्रदेश को यह सौगात मिली है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि विभाग के अधिकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के संपर्क में थे। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों जैसे पांगी, भरमौर, लाहुल-स्पीति और किन्नौर में उन कच्ची सडक़ों को पक्का करने का काम भी बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा, जोकि प्रदेश के विकास में एक नई गाथा लिखने का काम करेगा।

हिमाचल प्रदेश में लगभग 2000 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है, जिस पर भारी यातायात है। इसलिए संबंधित संस्थाओं को इन सडक़ों के रखरखाव और मरम्मत के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रदेश में हर साल लगभग 15000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। यदि इस कचरे को सडक़ों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले तारकोल में मिश्रित किया जाए, तो इससे सडक़ों की गुणवत्ता में सुधार होगा, खर्च कम होगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अलावा, सडक़ों के निर्माण या मरम्मत के लिए बजट में उचित राशि आवंटित करनी चाहिए। हर साल कुछ सडक़ों का भूमि पूजन होता है, लेकिन लंबे समय तक काम शुरू नहीं होता, जिससे जनता में असंतोष उत्पन्न होता है। अनुमान के अनुसार, सरकार को एकमुश्त बजट आवंटन करना चाहिए जिससे समय पर कार्य पूरा हो सके। शिमला-मटौर फोरलेन (रानीताल से चील बहल) का उन्नयन कार्य एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इस परियोजना का कुछ हिस्सा पहले ही खोदा जा चुका है और निर्माण कार्य अभी कुछ हिस्सों में चल रहा है, जिससे लोगों को धूल-मिट्टी और अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित संस्था को इस कार्य को निर्धारित मानकों, चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। गुम्मर, देहरियां, पड़ोली-कोहला और बस्दी कोहाला जैसे स्थानों पर सडक़ों की सतह नीचे चली गई है जिससे स्थानीय रास्तों और संपर्क सडक़ों को नुकसान हो रहा है। दुकानदारों और स्थानीय निवासियों को असुविधा हो रही है। अतः संबंधित विभाग को इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। अंततः, हिमाचल प्रदेश में सडक़ों के सुधार और विस्तार के लिए सरकार और जनता के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

अधिक से अधिक जनसहयोग और उचित बजट आवंटन से ही प्रदेश में सडक़ नेटवर्क को बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सकता है। सडक़ें न केवल राज्य के विकास की धारा को तेज करती हैं, बल्कि नागरिकों की जीवनशैली और आर्थिक गतिविधियों में भी सुधार लाती हैं। अच्छी सडक़ें रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं, व्यापार को बढ़ावा देती हैं और पर्यटन को भी आकर्षित करती हैं, जिससे राज्य की समृद्धि में योगदान होता है। इसके अलावा, इन सडक़ों के माध्यम से आपातकालीन सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान हो जाती है, जो कि ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, सडक़ों का विकास सिर्फ एक बुनियादी ढांचे का सुधार नहीं, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए एक अहम कदम है। सडक़ें प्रदेश के विकास के लिए एक तरह से नाडियों का काम करती हैं। अगर सडक़ नेटवर्क बढिया होगा, तो विकास गतिविधियों को तेजी से चलाया जा सकता है। सडक़ों के माध्यम से विकास की गाड़ी सरपट दौड़ती है, यह एक सर्वमान्य तथ्य है। अतः सडक़ों का उद्धार होना चाहिए।

विजय गर्ग

बीमार होने पर खुद डॉक्टर न बनें !

बैक्टीरियल इफक्शन से होने वाली बीमारियों को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चिकित्सक की सलाह के बिना इनका सेवन करना नुकसान पहुंचा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार, छोटी-छोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करने से उनका शरीर पर पड़ने वाला असर कम हो सकता है। पिछले कुछ सालों में वायरस अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, जिन पर कई एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाएं अब काम नहीं करतीं। जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, बैक्टीरिया और कवक उन दवाओं के प्रति भी प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं, जो सालों से कारगर रही हैं।

● क्या है माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आजकल बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए दी जाने वाली दवाओं का असर काफी कम हो रहा है। इस स्थिति को माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्थिति तब आती है, जब बैक्टीरिया,

वायरस, फंगी और पैरासाइट्स समय के साथ अपने स्वरूप को बदल लेते हैं। इस स्थिति में एंटीबायोटिक (एंटीमाइक्रोबियल) दवाओं का असर या तो बहुत कम होता है। या फिर बिल्कुल नहीं होता है, जिस वजह से संक्रमण का इलाज करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में बीमारी फैलने की आशका और अन्य समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं, जिसमें स्टीवन्स जॉनसन सिंड्रोम बेहद आम है। इस सिंड्रोम में मुंह, चेहरे और छाती पर दाने निकल आते हैं। यह जानलेवा भी हो सकता है।

● किन बातों का रखें ध्यान अगर आपको चिकित्सक ने एंटीबायोटिक दवाएं खाने की सलाह दी है तो सही मात्रा और समय पर ही दवा लें। अपने अनुसार कभी भी दवाओं की डोज बढ़ाना, कम करना या इनका सेवन बंद नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी दवा का उपयोग करने के बाद बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो भी कोर्स पूरा करें, क्योंकि दवा लेने से प्रारंभिक स्तर पर आराम तो आ जाता है, लेकिन संक्रमण पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं। कोर्स बीच में छोड़ने से सूक्ष्म जीव धीरे-धीरे उस दवा के प्रति प्रतिरोध क्षमता हासिल कर लेते हैं और अगली बार जब आप बीमार होते हैं तो वह दवा असर नहीं करती है। इसके अलावा कई लोग दोबारा बीमार पड़ने पर भी पहली बार डॉक्टर द्वारा बताई हुई दवाओं का सेवन कर लेते हैं, जो नुकसान पहुंचा सकता है। यह जरूरी नहीं कि लक्षण समान हों तो बीमारी भी समान ही हो। ऐसे में उचित दवा का सेवन न करने से समस्या अधिक बढ़ सकती है। हर एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल अलग-अलग होता है। इसलिए चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही एंटीबायोटिक दवाओं की डोज लें। जल्दी ठीक होने के लिए ओवरडोज लेने से भी बचना चाहिए।

शेयर मार्केट में अनिश्चतता का माहौल, क्या फार्मा फंड्स में दांव लगाना रहेगा सही?

परिवहन विशेष न्यूज

एक्सपर्ट के मुताबिक फार्मा या हेल्थ सेक्टर से जुड़े फंड्स की भविष्य की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। भारत में आबादी लगातार बढ़ रही है। बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इससे फार्मा सेक्टर काफी आगे बढ़ेगा। वैश्विक फार्मा क्षेत्र में भारत की बढ़ती धमक सरकार की नीतियां कुछ ऐसी वजहें है जिसके आधार पर इस सेक्टर को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं।

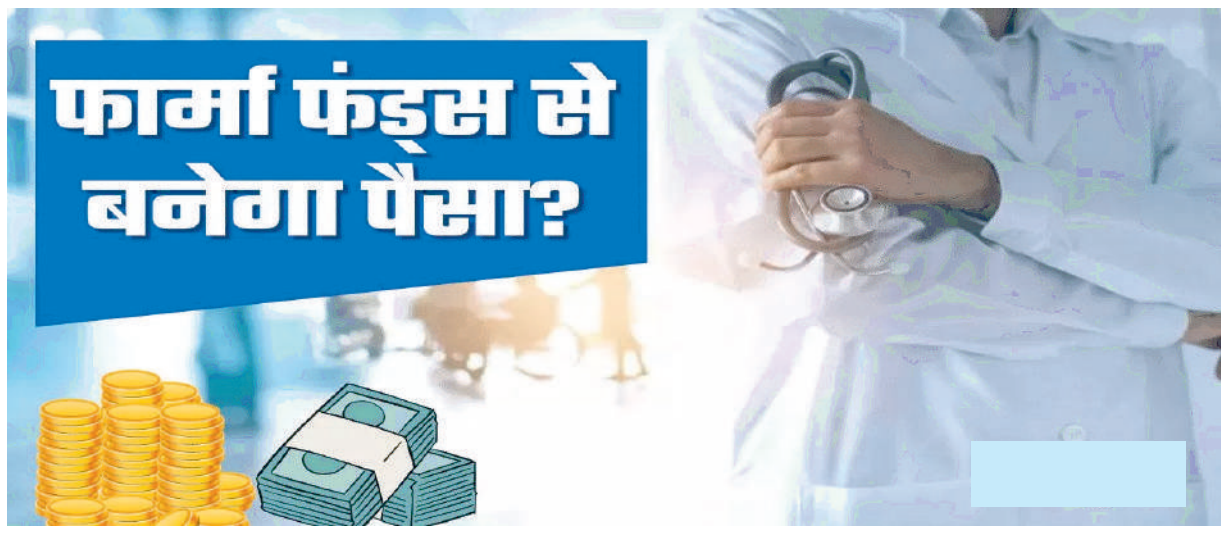

नई दिल्ली। शेयर बाजार में अस्थिरता का माहौल है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ने में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। ताजे आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर, 2024 में 41,224 करोड़ रुपये का निवेश म्यूचुअल फंड्स में किये गये हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश की जाने वाली मासिक राशि का आंकड़ा 25,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है।

वैसे तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय शेयर बाजार की तेजी ने हर श्रेणी के म्यूचुअल फंड (एमएफ) के निवेशकों को मालामाल किया है। हाल के हफ्तों में जिस तरह से शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है उससे यह सवाल उठ रहा है कि किस सेक्टर के एमएफ निवेशकों के लिए ज्यादा सुरक्षित हैं या जो मौजूदा अनिश्चितता के इत्तर निकट भविष्य में बेहतर निवेश देने की क्षमता रखते हैं।

इस बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि फार्मास्यूटिकल्स या हेल्थ सेक्टर से जुड़े फंड्स की भविष्य की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। भारत में जनसंख्या में हो रही लगातार वृद्धि, वैश्विक फार्मा क्षेत्र में भारत की बढ़ती धमक, सरकार की नीतियां कुछ ऐसी वजहें है जिसके आधार पर इस सेक्टर की भारत आधारित म्यूचुअल फंड को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं और निवेशकों को अपने कुल फंड आंवटन का 20 फीसद तक हिस्सा इसमें डालने की सलाह दी जा रही है।

फार्मा फंड पर क्यों लगाएं दांव?

पीजीआईएम इंडिया एसेट मैनेजमेंट के सीईओ अजीत मेनन का कहना है कि, "कम लागत, इनोवेशन, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बढ़ती जागरूकता, बढ़ता विदेशी निवेश, लगातार बढ़ रहे मेडिकल टूरिज्म और अन्य कई फैक्टर के चलते निवेशकों को फार्मा फंड में निवेश करने का लाभ मिलेगा।"

पीजीआईएम इंडिया एसेट मैनेजमेंट के आनंद पद्मनाभन अंजेनेयन, सीनियर फंड मैनेजर (इक्विटीज) का कहना है कि, "इस सेक्टर की एक खास बात यह है कि कीमत में बदलाव से डिमांड पर कुछ खास असर नहीं होता है। जिसके चलते प्राइ¨सग पावर बेहतर होती है, खासकर महंगाई के माहौल का भी कोई असर नहीं होता। यह एक निवेशक को लंबी अवधि में अपनी पूंजी बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।"

पीजीआईएम ने पिछले हफ्ते इंडिया हेल्थकेयर फंड लांच किया है। पिछले दो वर्षों के भीतर इस तरह के कई फार्मा फंड्स लांच किये गये हैं। इस साल औसतन 44 फीसद का रिटर्न ये दे रहे हैं।

फार्मा में जल्द आत्मनिर्भर बनेगा भारत

कुछ विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि कोविड काल के बाद भारत ने अपने घरेलू फार्मास्यूटिकल निर्माण सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान शुरू किया था उसका असर आने में दो-तीन वर्ष लगेंगे। भारत अभी फार्मा का एक बड़ा निर्यातक है लेकिन इसके लिए जरूरी कच्चा माल वह आम तौर पर चीन से आयात करता है। अब भारत सरकार की मदद से कच्चे माल को तैयार करने का काम भी भारत में करने की कोशिश शुरू हुई है।

भारत अपनी जरूरत का 50 फीसद बल्क ड्रग्स की आपूर्ति भी घरेलू सेक्टर से पूरी करना शुरू कर देगा तो इसका व्यापक असर होगा। इससे भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर और ज्यादा सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की आपूर्ति शुरू कर सकती हैं। वैसे निवेशकों को यह सुझाव दिया जा रहा है कि वह अपने कुल फंड आवंटन का 10-20 फीसद तक फार्मा फंड में करने से शुरूआत करें।

निवेश के लिए हो जाएं तैयार, नए साल में खुलेंगे कई दिग्गज कंपनियों के आईपीओ

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। इस साल शेयर बाजार में कई कंपनी के आईपीओ लिस्ट हुए। इन आईपीओ ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अब जल्द ही नया साल यानी 2025 शुरू होने वाला है। इस साल भी कई दिग्गज कंपनियों का आईपीओ लॉन्च होगा।

अगर आप भी आईपीओ में निवेश करते हैं तो हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि साल 2025 में कौन-से आईपीओ लॉन्च हो सकते हैं।

रिलायंस जियो

रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस जियो का आईपीओ आ सकता है। आपको बता दें कि सितंबर 2016 में जियो लॉन्च हुआ था। इसके बाद जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में अपना दबदबा कायम कर दिया। लॉन्च के समय जियो ने फ्री वॉयस कॉल और डेटा पैकेस ऑफर किया था। इस ऑफर ने ग्राहकों को आकर्षित किया। आज देश के ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में जियो पॉपुलर है।

अब निवेशकों की नजर रिलायंस जियो के आईपीओ पर बनी हुई है। निवेशकों को उम्मीद है कि 2025 में कंपनी का आईपीओ खुल सकता है। इस साल जियो ने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी की थी। कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाने और बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है।

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

टाटा मोटर्स (Tata Motors) की इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांच टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Tata Passenger Electric Mobility-TPEML) का आईपीओ भी साल 2025 में आ सकता है। TPEML की स्थापना 2021 में हुई थी। Ford India को टेकओवर करके टाटा ग्रुप ने इसका नाम TPEML दे दिया। टाटा ग्रुप ने यह टेकओवर ईवी सेक्टर (EV Sector) में विस्तार करने के लिए किया था। टाटा मोटर्स ने TPEML के जरिये कई ई-मॉडल जैसे- Nexon EV and Tiago EV को लॉन्च कर दिया है। भारत के ईवी सेक्टर मार्केट में इन मॉडल की हिस्सेदारी 80 फीसदी है।

अब निवेशकों की नजर रिलायंस जियो के आईपीओ पर बनी हुई है। निवेशकों को उम्मीद है कि 2025 में कंपनी का आईपीओ खुल सकता है। इस साल जियो ने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी की थी। कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाने और बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है।

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांच टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Tata Passenger Electric Mobility-TPEML) का आईपीओ भी साल 2025 में आ सकता है। TPEML की स्थापना 2021 में हुई थी। Ford India को टेकओवर करके टाटा ग्रुप ने इसका नाम TPEML दे दिया। टाटा ग्रुप ने यह टेकओवर ईवी सेक्टर (EV Sector) में विस्तार करने के लिए किया था। टाटा मोटर्स ने TPEML के जरिये कई ई-मॉडल जैसे- Nexon EV and Tiago EV को लॉन्च कर दिया है। भारत के ईवी सेक्टर मार्केट में इन मॉडल की हिस्सेदारी 80 फीसदी है।

क्लेम और ट्रैक करना हुआ आसान, प्रॉविडेंट फंड के लिए लागू हो गए नए नियम

ईपीएफओ इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप भी ईपीएफओ में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। ईपीएफओ ने क्लेम प्रोसेस क्लेम ट्रैक करने और पासबुक चेक करने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए निर्देश जारी किया है। नए नियम लागू होने से मेंबर्स को सुविधा होगी। पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड (Provident Fund-PPF) के नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियमों के लागू होने के बाद क्लेम प्रोसेस, क्लेम ट्रैक करना और पासबुक चेक करने का तरीका आसान हो गया है। इस नियम के लागू होने के बाद ईपीएफ मेंबर्स को काफी सुविधा मिलेगी।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार पेमेंट ब्रिज और 100% बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर दिये हैं। इस निर्देश के बाद नियोक्ताओं और कर्मचारियों को रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ELI) योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी।

नए नियमों का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को 30 नवंबर 2024 से पहले एक जरूरी काम निपटाना होगा।

UAN को करें एक्टिवेट

नए कर्मचारियों के साथ पुराने कर्मचारियों को भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए उन्हें आधार बेस्ड OTP प्रोसेस के जरिये यूएएन को एक्टिवेट करना होगा। UAN एक्टिव होने के बाद ईपीएफओ मेंबर को सभी ऑनलाइन सर्विस सुविधा का लाभ उठाने में आसानी होगी। जी हां, UAN के एक्टिव होने के बाद नीचे बताए गए सर्विस का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं-

- प्रॉविडेंट फंड अकाउंट को मैनेज करना
- PF पासबुक शो और डाउनलोड करना
- ऑनलाइन क्लेम सबमिट करना
- पर्सनल डिटेल्स अपडेट करना
- क्लेम को ट्रैक करना

अब मेंबर ईपीएफओ की 24/7 सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उन्हें ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी।

केंद्रीय कर्मचारी कर रहें इंतजार! आठवें वेतन आयोग लागू होते ही कितनी बढ़ेगी सैलरी

8वें वेतन आयोग अभी 7वां वेतन आयोग लागू है। अब केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में शानदार तेजी देखने को मिलेगी। सैलरी के साथ पेंशन राशि में भी वृद्धि होगी। आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा? इस आर्टिकल में इसका जवाब जानते हैं।

नई दिल्ली। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत डीए हाइक (DA Hike) और वेतन में वृद्धि मिल रही है। अब कर्मचारी आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की आस लगा रहे हैं।

सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगले साल के आम बजट 2025 (Budget 2025) में आठवें वेतन आयोग लागू हो सकता है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों को उम्मीद है कि इसके लागू होने के बाद न्यूनतम सैलरी में 186 फीसदी की वृद्धि हो सकती है।

कितनी हो जाएगी सैलरी

वर्तमान में 7वां वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 6,000 रुपये की वृद्धि हुई थी। विशेषज्ञों के अनुसार आठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। इसमें 29 बेसिस प्वाइंट बढ़ने की उम्मीद है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 को लागू करती है तब कर्मचारियों की सैलरी में 186 फीसदी की वृद्धि के साथ करीब 51,480 रुपये हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर के बढ़ जाने से कर्मचारियों के साथ पेंशनधारक को भी लाभ होगा। दरअसल, इसमें इजाफा होता है तो पेंशन राशि भी बढ़ जाएगी।

पेंशनर्स को उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पेंशन 186 फीसदी बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। वर्तमान में पेंशन राशि 9,000 रुपये है। 25,740 रुपये पेंशन तब होगी जब फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है।

कब लागू होगा 8th Pay Commission

अभी तक आठवें वेतन आयोग के लागू होने की अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी घोषणा अगले वित्त वर्ष के बजट (Budget 2025-26) में हो सकता है। वैसे तो कर्मचारियों ने पिछले बजट में आठवें वेतन आयोग लागू करने की मांग की थी।

इस साल दिसंबर में नेशनल काउंसिल (National Council) की मीटिंग है। इस मीटिंग में आठवें वेतन आयोग के लागू होने की बात साफ हो सकती है। वैसे तो यह मीटिंग नवंबर में होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे दिसंबर के लिए पोस्टपौंड कर दिया गया।

7th Pay Commission कब बना

7वां वेतन आयोग के बनने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में शानदार तेजी देखने को मिली थी। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बनी थी, लेकिन यह 1 जनवरी 2016 में लागू हुआ था। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई।

वैसे तो हर 10 साल में नया वेतन आयोग का गठन होता है। हालांकि, इसको लेकर

ग्रेच्युटी के लिए नॉमिनी बनाने का क्या है प्रोसेस, ताकि परिवार में न हो कोई विवाद

ग्रेच्युटी के लिए नॉमिनी चुनना जरूरी है। इससे परिवार के सदस्यों को कर्मचारी की मृत्यु के बाद ग्रेच्युटी रकम पाने में मदद मिलती है। नॉमिनी चुनने से रकम के बंटवारे को लेकर परिवार में विवाद की गुंजाइश भी कम हो जाती है। नॉमिनी चुनने की प्रोसेस भी काफी आसान है। आइए जानते हैं कि आप नॉमिनी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं।

नई दिल्ली। किसी भी संस्थान में लंबे वक्त तक काम करने के बाद कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलती है। यह रकम एक तरह से उनकी वफादारी का इनाम होती है। ग्रेच्युटी अमूमन रिटायरमेंट के बाद मिलती है, लेकिन अगर आप एक तय समय के बाद जॉब छोड़ते हैं, तब भी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी।

लेकिन, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान असमय मृत्यु हो जाती है, तो ग्रेच्युटी की रकम उसके नॉमिनी को मिलती है। आइए जानते हैं कि ग्रेच्युटी के लिए नॉमिनी कैसे चुना जाता है।

नॉमिनी चुनना क्यों जरूरी है?

ग्रेच्युटी के रूप में एकमुश्त अच्छी-खासी रकम मिलती है। कर्मचारी के न रहने की स्थिति में इस रकम को लेकर परिवार में विवाद भी हो सकता है। इससे बचने के लिए नॉमिनी नियुक्त करना काफी जरूरी है। आप एक से अधिक नॉमिनी चुनकर यह भी तय कर सकते हैं कि ग्रेच्युटी का रकम का बंटवारा कैसे होगा।

ग्रेच्युटी नॉमिनी कैसे चुनते हैं?

सभी कर्मचारियों को अपना नॉमिनी चुनने का अधिकार है। आप फॉर्म एफ का इस्तेमाल करके अपना नॉमिनी चुन सकते हैं। इसे आपको अपनी कंपनी के पास जमा करना होता है। आप एक या इससे अधिक लोगों को भी नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी को आप मनमुताबिक बदल भी सकते हैं।

नॉमिनी किसे बनाया जा सकता है?

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत आप मुख्य तौर पर पारिवारिक सदस्यों को ही नॉमिनी बना सकते हैं। इनमें पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता, आश्रित सास-ससुर, बेटे की विधवा और उसके बच्चे शामिल होते हैं। आप परिवार के एक से अधिक सदस्यों को भी नॉमिनी बना सकते हैं।

नॉमिनी न होने की स्थिति में क्या होगा?

अगर कर्मचारी ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है, तो उसकी मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी के पैसे उसके कानूनी वारिस को दे दिए जाएंगे। हालांकि, इसमें वक्त लग सकता है और कानूनी अड़चन भी हो सकती है। उत्तराधिकारी को वाजिब कानूनी दस्तावेज भी पेश करने पड़ सकते हैं।

नॉमिनी नियुक्त करने का प्रोसेस

आप अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से फॉर्म एफ लें। इसमें कुछ जानकारियां देनी होती हैं। जैसे कि नॉमिनी का नाम और उससे रिश्ता। अगर एक से अधिक नॉमिनी है, तो किसको कितना हिस्सा मिलना है। फिर आपको गवाह के साथ अपने हस्ताक्षर करके एचआर डिपॉर्टमेंट या नामित अधिकारी के पास जमा करना होगा।

सिल्वर ईटीएफ़ दे रहा है गोल्ड से ज्यादा रिटर्न, निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बन रहा सिल्वर ईटीएफ

निवेश के लिए सिल्वर ईटीएफ भी काफी अच्छा ऑप्शन है। हाल में आए रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में गोल्ड ईटीएफ से ज्यादा रिटर्न सिल्वर ईटीएफ ने दिया है। ऐसे में निवेशकों को यह ऑप्शन काफी पसंद आ रहा है। सिल्वर ईटीएफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) चार गुना से ज्यादा बढ़ा है। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। सिल्वर ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) यानी चांदी ईटीएफ (Silver ETF) निवेशकों के बीच निवेश के लिए काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। यह ईटीएफ 2022 में लॉन्च हुआ था। यही कारण है कि बीते एक वर्ष में सिल्वर ईटीएफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) चार गुना से ज्यादा बढ़ा है।

रेटिंग एजेंसी इक्रा के विश्लेषकों का कहना है कि चांदी एक कीमती धातु है और इसमें घरेलू महंगाई के दबाव और भूराजनीतिक अनिश्चितता के दौर से निपटने की क्षमता है। यही कारण है कि सिल्वर ईटीएफ के प्रति निवेशकों का आकर्षण बढ़ रहा है। आइए जानते हैं कि बीते एक वर्ष में सिल्वर ईटीएफ का एयूएम कितना बढ़ा है और इस दौरान इनमें कितना निवेश हुआ है।

कितना है सिल्वर ईटीएफ का एयूएम

सिल्वर ईटीएफ का एयूएम 12,331 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह अक्टूबर 2024 में2,844.76 करोड़ रुपये था। वहीं, सिल्वर ईटीएफ का एयूएम अक्टूबर 2023 के अंत में 215 प्रतिशत बढ़ी है। अगर सिल्वर ईटीएफ के फोलियो (खातों) की संख्या की बात की जाए तो एक वर्ष में इसमें 1.42 लाख फोलियो जुडे. हैं। इसके बाद कुल फोलियो 4.47 लाख हो गई। अक्टूबर 2024 के अंत में सिल्वर ईटीएफ फोलियो में 643.10 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। बीते एक वर्ष के दौरान सिल्वर ईटीएफ में कुल निवेश 24 प्रतिशत बढ़ा।

कितना मिला रिटर्न

सिल्वर ईटीएफ ने एक महीने में 7.57, तीन महीने में 16.02, छह महीने में 20.25 और एक वर्ष 32.49 फीसदी का रिटर्न दिया है। बीते एक वर्ष के दौरान विभिन्न अवधि में सिल्वर ईटीएफ ने गोल्ड ईटीएफ से बेहतर रिटर्न दिया है।

त्रिसुलिआ ब्रिज पर बैटरी गाड़ी जली

त्रिसुलिआ ब्रिज पर बैटरी गाड़ी जली

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : कटक ट्राइडेंट नेताजी सुभाष बोस ब्रिज पर बैटरी स्कूटी जल गई।आज सुबह बरंग फकीरपाड़ा गांव के सिद्धार्थ प्रसाद साहू किसी काम से अपनी ई-बाइक से घर से कटक जा रहे थे, तभी त्रिशूला ब्रिज पर उनकी बाइक में अचानक आग लग गई। सिद्धार्थ ने देखा कि बाइक में आग लगी हुई है और वह बाइक छोड़कर चला गया। इसके बाद उन्होंने बरंगे अग्निशमन विभाग को सूचित किया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जबकि गली पूरी तरह जली हुई मिली।

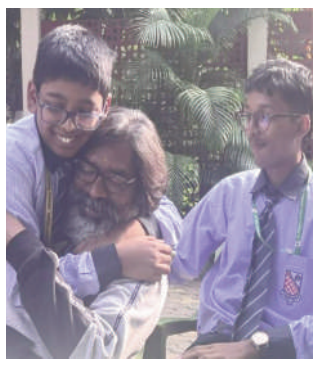

मुख्यमंत्री हेमंत ने चुनाव जीतने के बाद बेटों के साथ तस्वीर साझा की

कार्तिक परिच्छा स्टेट हेड

सरायकेला, चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भावुक भरे एक तस्वीर को साझा किया है । हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन , भाई बसन्त सोरेन समेत जे एम एम गठबंधन सरकार की चुनाव में अपार सफलता व चुनाव जीतने के बाद बेटों के साथ यह तस्वीर सोशल साईट पर डाला ।जिसमें अपने दोनों बेटों के साथ उन्होंने लिखा -मेरी शक्ति ।यह तस्वीर अब वायरल हो रही है ।

महाराष्ट्र में जीत से गदगद मोदी, बोले- जनता ने वंशवाद को

महाराष्ट्र की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। हालत ये है कि कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। आज महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा है।

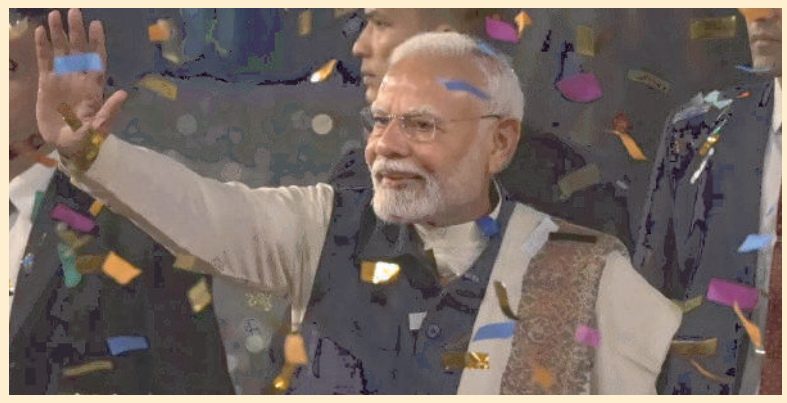

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि ताजा चुनावी नतीजों ने विकास के संदेश को समर्थन दिया है और कांग्रेस व उसके सहयोगियों द्वारा फैलाई गई झूठ और विश्वासघात की राजनीति को धूल चटाई है। राष्ट्र को प्रथम रखने वाले दलों को मतदाताओं ने स्वीकारा है जबकि कुर्सी को प्राथमिकता पर रखने वाले दलों को नकार दिया है। मतदाता अस्थिरता नहीं चाहते हैं।

एक हैं तो सेफ हैं

यहां भाजपा मुख्यालय में एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव और विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों में विभाजनकारी ताकतों, नकारात्मक और वंशवादी राजनीति को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने स्थिरता के लिए वोट दिया है और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने वालों को करारा सबक सिखाया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र चुनाव का संदेश एकता का है और यह 'एक हैं तो सेफ हैं' के नारे पर भी मुहर लगाता है।

सभी वर्गों ने भाजपा को वोट दिया

मोदी ने कहा कि वह झारखंड के लोगों के सामने नतमस्तक हैं और भाजपा राज्य के विकास के लिए और अधिक उत्साह से काम करेगी। पीएम ने कहा कि 'एक हैं तो सेफ हैं' पूरे देश के लिए महामंत्र बन गया है और इसने उन लोगों को दंडित किया है जो देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटना चाहते थे। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों ने भाजपा को वोट दिया है।

राष्ट्र प्रथम में विश्वास

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके तंत्र ने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ फैलाकर वे एससी, एसटी और ओबीसी को छोटे-छोटे समूहों में बांट सकते हैं। यह उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। लोगों ने विभाजनकारी ताकतों को धूल चटा दी है। कांग्रेस और उसके सहयोगी देश के मूड की बदलती वास्तविकताओं को समझने में विफल रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदाता अस्थिरता नहीं चाहते हैं और वे राष्ट्र प्रथम में विश्वास करते हैं और कुर्सी पहले का सपना देखने वालों को पसंद नहीं करते हैं।

नड्डा बोले- जनता ने तुष्टीकरण की राजनीति को नकारा

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के उप चुनावों में पार्टी की जीत को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि लोगों ने देश के विकास के लिए पीएम के दृष्टिकोण पर फिर अपनी मुहर लगा दी है। विपक्ष की विभाजनकारी और तुष्टीकरण की राजनीति को लोगों ने नकार दिया है।

घुसपैठ के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे

भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने झारखंड में भाजपा को मिले जनादेश को स्वीकार किया और कहा कि उनकी पार्टी राज्य में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। बांग्लादेश से घुसपैठ के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेगी। जो लोग देश को जाति के आधार पर बांट रहे थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे, वे इन चुनावों में औंधे मुंह गिरे हैं।

उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा

उन्होंने कहा कि इन चुनावों और हाल ही में हरियाणा में हुए चुनावों के नतीजों ने आईएनडीआई गठबंधन के उन लोगों को जवाब दिया है जो इस भ्रम में जी रहे थे कि वे तुष्टीकरण की राजनीति कर, लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटकर सत्ता हासिल कर लेंगे। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले राजग ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी, लेकिन ठाकरे ने सत्ता के लालच के आगे झुककर महाराष्ट्र के लोगों के साथ विश्वासघात किया।

कानपुर में काम नहीं आया कटोगे तो बटोगे का नारा, सीसामऊ में फिर फहरा सपा का झंडा

- सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने भाजपा के सुरेश अवस्थी को 8629 वोटो से हराया ,भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को मिले 61037
- 1996 में आखिरी बार सीसा मऊ में जीती थी भाजपा ,इसके बाद से समाजवादी पार्टी की ही हो रही जीत

सुनील बाजपेई

कानपुर। इस बार के उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी रही यहां के सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा फिर गाढ़ दिया है। यहां आज शनिवार को ही मतगणना में समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी ने भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी को 8629 वोटो से हरा दिया। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को 69666 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 61037 वोट मिले हैं। बसपा प्रत्याशी बीरेंद्र शुक्ला ने 1409 वोट हासिल किए हैं। संपन्न कराए गए उप चुनाव में सीसामऊ में 49.06% मतदान हुआ था, जो पिछले 12 साल में सबसे कम रहा।

वहीं इस जीत को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों में भारी उत्साह और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में निराशा भी देखी गई।

सपा की जीत के बाद पार्टी कार्यालय में भी जीत का जश्न रहा। एक दूसरे को जीत की बधाई देते हुए समाजवादी पार्टी के लोगों ने इरफान सोलंकी जिंदाबाद, नसीम सोलंकी जिंदाबाद, जेल के ताले टूटेंगे इरफान भैया छूटेंगे... जैसे नारे भी लगाए।

वहीं भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने काउंटिंग खत्म होने से पहले ही हार स्वीकार करते हुए इसकी वजह भीतरघात बताया। कहा- हिंदू वोट अगर न बंटता तो हमारी जीत होती।

अवगत कराते चलें कि शुरुआती रुझान से ही सपा यहां आगे चल रही थी।

दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से चुनाव जीती नसीम सोलंकी ने कहा- सीसामऊ की जनता ने मेरे साथ इंसाफ किया है। सबसे पहले पति से मुलाकात करने जाऊंगी। इस बीच उन्होंने आरोप भी लगाया कि पुलिस और प्रशासन की दखल न होती तो जीत और बड़ी होती। अभी 8-साढ़े आठ हजार वोटों से जीती हूं, वरना 28 हजार वोटों से जीतती।

याद रहे कि इरफान सोलंकी को सजा हुई तो उनकी विधायकी चली गई जिसके लिए कराए गए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया था।

जहां तक सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी के कब्जे का सवाल है। सीसामऊ सीट में भाजपा ने अंतिम बार 1996 में जीत दर्ज की थी। तब भाजपा के राकेश सोनकर यहां से चुनाव जीते। परिसीमन के बाद यह सीट मुस्लिम बहुल हो गई। पिता हाजी मुस्ताक सोलंकी की राजनीतिक विरासत संभाल रहे इरफान सोलंकी आर्य नगर सीट से सीसामऊ शिफ्ट हो गए। इसके बाद 2012 में उन्होंने सीसामऊ से जीत दर्ज की। फिर 2017 और 2022 का चुनाव जीत हैट्रिक लगाई।

भारतीय समृद्धि,संस्कृति विरासत विविधताओं का कूटनीति में ज़बरदस्त आगाज़-हर तोहफ़ा कुछ कहता है

भारत की समृद्ध सांस्कृति की विरासत विविधता व कलाओं को विश्व के मेज़बान देश व राष्ट्रअध्यक्षों तक पहुंचाने का अद्भुत नायाब तरीका

भारतीय संस्कृतिक़ विरासत की विविधताकी सौगातों से पीएम द्वारा अपनी विदेश यात्राओं में मेज़बान देशों को परिचित कराने में अद्भुत योगदान-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर आदि अनादि काल से भारत को सोने की खान कहा जाता रहा है, इसका कारण न केवल यहां के भरपूर प्राकृतिक संसाधन बौद्धिक क्षमता बल्किसांस्कृतिक विरासत संस्कारों का खजाना सहित हमारी सांस्कृतिक धरोहर विरासत के अनेक संसाधन भी भारत में है,जो भारत की समृद्धि का विकास करने में काफी अहम रोल अदा कर रहा है,इसलिए पूरे विश्व की नज़रे भी भारत की ओर उठी है,जिसका भारत सटीकता से स्वागत कर कूटनीतिक चर्चाओं के अतिरिक्त दुनियाँ के मेज़बान देशों व राष्ट्रीध्यक्षों को भारतीय संस्कृति की विविधता की सौगातें दी जा रही है,जिसका विशाल समृद्ध दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा।वर्तमान में भारत के प्रति विश्व का सहयोगात्मक भाव विकसित हो रहा है जो सटीक उदाहरण है, यह बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पीएम 16 से 21 नवंबर 2024 की सफ़ल विदेश यात्रा पूर्ण कर 22 नवंबर 2024 को देर रात भारत पहुंचे, जिसमें नाइजीरिया ब्राज़ील गुयाना की यात्रा है,परंतु आज हम चर्चा का विषय पीएम द्वारा भारत के अनेकों राज्यों की सांस्कृतिक धरोहरों विविधताओं को इन राष्ट्रीअध्यक्षों, मेज़बान देशों को उपहार में देकर उन्हें मोहित कर दिया है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारतीय समृद्ध संस्कृति की विरासत विविधताओं का कूटनीति में जबरदस्त आगाज़,हर तोहफा कुछ कहता है !

साथियों बात अगर हम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की विविधता व कलाओं को विश्व के मेजबान देश व अनेक राष्ट्रध्यक्षों तक पहुंचाने के अद्भुत नायाब तरीके की करें तो,भारत के पीएम जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, वह कूटनीतिक चर्चाओं से इतर देश की समृद्ध संस्कृति की विविधता की सौगात भी अपने साथ ले जाते हैं और उससे मेजबान देशों का परिचय कराते हैं। यह देश की सांस्कृतिक विरासत और कलाओं के जरिए संबंधों को कूटनीति की सीमाओं के परे नया आयाम देने में मददगार साबित होता है। पिछले दिनों पीएम नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा पर गए थे।वह अपने साथ मेजबान राष्ट्राध्यक्षों के लिए देश के हर कोने से उपहार लेकर गए थे। इनमें आठ कलाकृतियां महाराष्ट्र से, पांच जम्मू-कश्मीर से, तीन-तीन आंध्र प्रदेश और राजस्थान से और दो झारखंड से थी।कर्नाटक, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश,बिहार, ओडिशा औरलद्दाख से भी एक-एक कलाकृतियां थी।महाराष्ट्र के उपहारों में सिलोफर पंचामृत कलश नाइजीरिया के राष्ट्रपति को दिया गया।यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पारंपरिक शिल्प कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है।तीन देशों की अपनी यात्रा के दौरान पीएम अपने साथ महाराष्ट्र से 8, जम्मू और कश्मीर के 5, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से 3-3, झारखंड से 2 और कर्नाटक तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और लद्दाख से 1-1 उपहार लेकर गए थे। पांच दिनों के दौरान कई देशों के 31 नेताओं से पीएम मोदी ने मुलाकात की तोद्विपक्षीय रिश्तों का एजेंडा आगे बढ़ाने के साथ-साथ इसबात का भी ख्याल रखा कि संबंधों में दोस्ती की महक और रंगत तोहफों के जरिए आगे तक जाए।

साथियों बात अगर हम पीएम की 16 से 21 नवंबर2024 विदेश यात्रा में उपहार के जरिए भारतीय संस्कृति की विरासत दिखाने की करें तो,इन नेताओं को पीएम ने दिए ये उपहार (1) पुणे के कलाकारों के हाथ से बना चांदी का ऊंट और प्राकृतिक खुरदरा नीलम ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज़ भारतीय पीएम से मुलाकात के बाद अपने साथ लेकर गए। वहीं पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात में भारत की ओर से उपहार में पारंपरिक डिजाइन के साथ नक्काशीदार चांदी का शतरंज सेट उन्हें दिया गया। (2) भारत और इटली के बीच रिश्तों की रौशनी के प्रतीक के तौर पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मैलोनी को भारतीय पीएम ने चांदी से बना मोमबत्ती स्टैंड उपहार में दिया। वहीं चांदी से ही बनानक्काशीदार फलों का एक कटोरा कैरीकॉम के महासचिव के लिए तैयार उपहार बास्केट में शामिल था। (3) गयाना की प्रथम महिला के लिए तोहफा कश्मीरी रंगत के साथ पहुंचा था। इसमें पपीयर माचे बॉक्स में रखी पश्मीना शॉल अब उनके घर की सजावट और दोनों देशों के संबंधों की गर्माहट का भी एहसास कराएगी।कश्मीर की खुशबू कैरीकॉम देशों के नेताओं को दिए गए कस्टमाइज्ड गिफ्ट हैम्पर में भी शामिल थी। उन्हें तोहफों के साथ कश्मीरी केसर भी भारत से उपाहार के तौर पर मिली है। (4)पीएम के विमान में पहुंचे राजस्थान के उपहारों शामिल सिल्वर फोटो फ्रेम अब अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ ब्यूनोस आयर्स पहुंच चुका है। वहीं राजस्थान के मकराना मार्बल से बना खास नक्काशीदार पिएट्रा ड्यूरा नॉर्वे के प्रधानमंत्री को भारत के साथ रिश्तों की याद दिलाता रहेगा। राजस्थान के शिल्पकारों की मेहनत और कारीगरी से तैयार सोने के काम वाली राज सवारी मूर्ति गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स के घर की शोभा बढ़ाएगी। भारतीय पीएम की गिफ्ट बास्केट में उत्तर भारत ही नहीं दक्षिण भारत के तोहफे भी विदेश पहुंचे। इस कड़ी में आंध्रप्रदेश कीमती पत्थरों से जड़ा सिल्वर क्लच पर्स ब्राजील के राष्ट्रपति की पत्नी को भेंट किया गया। वहीं कैरीकॉम देशों के नेताओं को दिए गए कस्टमाइज्ड गिफ्ट हैम्पर में आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में उगाई जाने वाली खास कॉफी को भी शामिल किया गया था। (5) नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति को हजारीबाग की सोहराय पेंटिंग दी गई जो पशु,पक्षी और प्रकृति के चित्रण के लिए जानी जाती है। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के लिए पीएम मोदी खोवर पेंटिंग लेकर पहुंचे थे जो झारखंड की आदिवासी कला और सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। (6) उपहारों की कड़ी में चिली के राष्ट्रपति को भारतीय पीएम ने उत्तरप्रदेश में बना लकड़ी का बारीक नक्काशीदार और उत्कीर्ण चांदी फोटो फ्रेम भेंट किया। वहीं कर्नाटक के छोटे से शहर चन्नपटना की विशिष्ट लकड़ी से बनी खिलौना ट्रेन उन्होंने गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के छोटे बेटे को दी। (7) फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को पीएम ने तमिलनाडु की प्रसिद्ध तंजावुर पेंटिंग भेंट की। इसे दोस्ती का इशारा कहिए या कूटनीति का संदेश, भारतीय पीएम ने फ्रेंच राष्ट्रपति को उस तमिलनाडु के कलाकारों की कला का नमूना भेंट किया जहां से सटे करईकल और पुदुचेरी इलाके में कभी फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारतीय समृद्धि, संस्कृति विरासत विविधताओं का कूटनीति में ज़बरदस्त आगाज़ -हर तोहफ़ा कुछ कहता है !भारत की समृद्ध सांस्कृति की विरासत विविधता व कलाओं को विश्व के मेज़बान देश व राष्ट्र अध्यक्षों तक पहुंचाने का अद्भुत नायाब तरीकाभारतीय संस्कृतिक़ विरासत की विविधता की सौगातों से पीएम द्वारा अपनी विदेश यात्राओं में मेज़बान देशों को परिचित कराने में अद्भुत योगदान है।

- क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यम सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

डीप स्टेट की अंतरराष्ट्रीय साजिश का शिकार तो नहीं बन रहे गौतम अदाणी

मनोज कुमार अग्रवाल

पिछले कुछ सालों में तेज़ी से उभरे भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी अक्सर विरोधियों के निशाने पर बने रहते हैं। देश के विपक्षी दल के नेता हो या सरकार के विरोधी आरोप हमेशा अदाणी पर लगाते हैं। हाल ही में अमेरिकी एजेंसियों द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोप से भारत सहित पूरी दुनिया में खलबली मचना स्वभाविक है, क्योंकि अदाणी ग्रुप का कारोबार पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। अमेरिकी एजेंसियों के तरफ से आरोप लगाए गए है कि अमेरिकी निवेशकों से लिए पैसों का इस्तेमाल कथित तौर पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया था। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर और प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा दायर किए गए आरोपों में अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी, उनके भतीजे सागर अदाणी और अदाणी ग्रीन एनर्जी के पूर्व सीईओ विनीत जैन पर सौर एनर्जी कॉन्ट्रेक्ट के लिए अपने हिसाब से शर्तों को लागू करने के लिए 2020 से 2024 तक एक योजना बनाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के ठेके हासिल करने के लिए उन्होंने भारतीय अधिकारियों को लगभग 2,250 करोड़ रुपये की रिश्वत खिलाई। अदाणी ग्रुप ने इन प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटाया था, यही वजह है कि अमेरिकी कोर्ट में उनके खिलाफ ये मामला आया है। इन प्रोजेक्ट से समूह को 20 वर्षों में करीब 2 अरब डॉलर के मुनाफे का अनुमान था। इस पूरे मामले में गौतम अदाणी, अदाणी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अदाणी, एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता, एज्योर पावर में सलाहकार रूपेश अग्रवाल अमेरिकी इश्युअर हैं। मामले के केंद्र में अदाणी ग्रीन एनर्जी और एक अन्य रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, एज्योर पावर द्वारा सरकारी स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था। देखा जाए तो इससे पहले अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे। यथा संभव समूह ने हिंडनबर्ग के तीखे हमलों का मुकाबला बखूबी किया था, लेकिन इस बार उसे जटिल विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, कारोबारी समूह ने रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों को निराधार कहकर खारिज किया है। कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद बताया है कि अभियोग में लगाए गए आरोप जब तक साबित नहीं हो जाते, तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है। सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। अदाणी ग्रुप के तरफ से कहा कि गया है कि कंपनी हमेशा शासन, पारदर्शिता और विनियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंपनी अपने हितधारकों, भागीदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि ग्रुप एक कानून का पालन करने वाला संगठन हैं, जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करता है। वैसे जिस प्रकार से आरोप लगे हैं तो अब अदाणी समूह के पास लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिये खुद को तैयार करने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता। हालांकि आर्थिक जानकारों का मानना है कि अदाणी पर आरोप अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत लगाया जा रहा है। इसके कई कारण भी सामने आ रहे हैं। भारत सरकार और कारोबारी जगत हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के समय को लेकर चिंतित हैं। रूसी मीडिया संस्थान स्पुतनिक की भारतीय शाखा स्पुतनिक इंडिया के मुताबिक, जानकार इसे 'डीप स्टेट' की साजिश मान रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 'डीप स्टेट' मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहता है। बांग्लादेश में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। जानकार मानते हैं कि बाजार नियामक संस्थान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट भी 'डीप स्टेट' की चालों की ही एक कड़ी है। उद्योग सूत्रों ने स्पुतनिक इंडिया को बताया है कि इसका मकसद भारतीय संस्थानों में विश्वास कमजोर करना है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में सफल मगर अमेरिका में नाकाम डीप स्टेट दोबारा अडानी के बहाने भारत पर बुरी नजर डाल रहा है। भारतीय अधिकारियों को हिंडनबर्ग रिसर्च की इस कोशिश के बारे में बताया गया है। उनका कहना है कि ये पश्चिमी ताकतों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने के प्रयास हैं। कहा जा रहा है कि 'डीप स्टेट' भारत की जड़ें हिलाने के लिए मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहता है। बाजार नियामक संस्थान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को भी 'डीप स्टेट' की चालों की ही एक कड़ी बताया जा रहा था। स्पुतनिक इंडिया ने वैश्विक उद्योग सूत्रों के हवाले से बताया है कि डीप स्टेट का मकसद भारतीय संस्थानों और कारोबारियों में जनता का विश्वास कमजोर करना है। बांग्लादेश समेत दक्षिण एशिया के कई देशों के अलावा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान साफ तौर पर यूएस डीप स्टेट की भूमिका देखी गई थी। अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचार के दौरान जानलेवा हमले के बाद सार्वजनिक तौर पर इसको लेकर गंभीर चिंता जताई थी। डीप स्टेट किसी भी राज्य के राजनीतिक नेतृत्व से अलग स्वतंत्र रूप से अपने निजी एजेंडे और लक्ष्यों के लिए काम करती है। पब्लिक स्फीयर में यह शब्द काफी ज्यादा नकारात्मक अर्थ रखता है और अक्सर इसका मकसद साजिश के सिद्धांतों से जुड़ा होता है। इससे साफ हो जाता है कि अदाणी के खिलाफ यह पूरा मामला साजिश भी हो सकता है, क्योंकि पिछले दशक में अदाणी समूह ने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों से लेकर पावर सेक्टर तक में तेजी से अपना कारोबार बढ़ाया है। इससे अमेरिका के साथ संबंधों पर भी असर पड़ने की संभावना है। दरअसल भारत के रूस से गहरे होते रिश्तों व चीन से सुधरते संबंधों के बीच अमेरिका व कनाडा समेत पश्चिमी देशों में भारत को लेकर वक्र दृष्टि देखी जा रही है। अदाणी प्रकरण को भी वर्तमान अमेरिकी सरकार व भारत के बीच तल्खी के आलोक में देखा जा रहा है। अमेरिका ने इससे पहले आरोप लगाया था कि भारत सरकार के एक कर्मचारी ने न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी नागरिक व सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश रची थी। बहरहाल, अब देखना होगा कि ट्रंप की ताजपोशी के बाद दोनों देशों के रिश्ते कैसे रहते हैं। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस मामले की पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि वास्तविक सच्चाई सामने आ सकें। साथ ही जिस प्रकार से विपक्ष अदाणी को घेरने में जुटा है, उसको इस प्रवृति से बाज आना चाहिए। विपक्ष को चाहिए कि वह इस मामले में अदाणी और सरकार को घेरने के बजाए वास्तविकता को समझे। यह याद रखना जरूरी है कि अभियोग में लगे आरोप सिर्फ आरोप हैं, और जब तक किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। भारत के विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता भी पीएम मोदी और अदाणी की दोस्ती का जिक्र कर तरह तरह के आरोप लगाते रहे हैं और यह सिलसिला चुनाव के दौर में बढ़ जाता है अब अमेरिका से भी इस तरह के विवाद को जन्म दिया जाना किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता है।

रेवड़ी कल्चर का यह बढ़ता परिदृश्य...

सत्ता के इस परिदृश्य में काम दम दंड भेद सब जायज है पर इतने वर्षों की राजनीति की रंगत में निखार आने से ज्यादा बंदरग क्यों होती जा रही है। कहीं जो इसका फायदा उठाते है उनके वारे-न्यारे हो हो जातें हैं। इसमें मध्यमवर्गीय परिवार ही का नुक़सान होता है जो ईमानदारी से आम नागरिक का फ़र्ज़ निभाता है। राजनीति रेवड़ी का यह क्या खेला हो रहा है हर तरफ खैरात बांटने वाले राजनेताओं की भीड़ लगी हुई है । कहीं लाड़ली लक्ष्मी है कहीं लाड़ली बहना वहीं मुफ्त इलाज मुफ्त अनाज सभी के लिए यह समझ से परे है ? मेहनतकश जनता जब अपना हक़ मांगेगा तो यह सरकारें नहीं दे पाएंगी। जिस प्रकार से कोई भी समान्य सी मिठाई को हर कोई लेना चहता है पर राजनीति के क्षेत्र में यह बहुत कामन बात हो गई है। हर राज्य में पूरे देश में इस के बिना मझधार पार होना वर्तमान समय में बहुत मुश्किल हो गया है। तभी तो हर एक पार्टी व राजनीतिक दलों को उनके मुखिया इस रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने में सभी आगे है। अगर इसके लिए उन्हें सरकार का खाजाना खाली करना पढ़ें तो भी इसकी चिंता किसी को नहीं है। वर्तमान समय में हर कोई इस मुफ्त की रेवड़ी की मिठास में घिरे जा रहें हैं। क्योंकि यह एक फार्मूला है जनमत को पाने का सस्ता व सुलभ संसाधन इसे कह सकते हैं। पहले मुफ्त की चीजों को लेने पर हर कोई नहीं आगे आता था जो योग्य यानी कमजोर गरीब मजदूर इस के लिए सही हकदार थे वहीं इसे लेते थे। वर्तमान में कुछ जिम्मेदारों ने इसे रेवड़ी बना दिया वह भी मुफ्त की । सभी को बांटना शुरू कर दिया। आमजन की मेहनत का पैसा उसके टेक्स पर चलती देश की अर्थव्यवस्था सभी ध्वस्त हो रही है। तभी तो आमजन ईमानदारी से टेक्स देता है । मुफ्त की बिजली पानी अन्य चीजें दोनों हाथों से बांटती यह सरकारें क्या बताना चाहतीं हैं ? वह भूल जातीं हैं कि यह पब्लिक है सब जानती है और यह उनका पैसा सभी के लिए है फिर क्यों मुफ्त की रेवड़ी बांटने में राजनेता अपनी वाह-वाही कर रहे हैं। ऐसा कल्चर ठीक नहीं है कोई भी प्रदेश हो मुफ्त की हर एक योजना में हर कोई लाईन में लगा हुआ है ऐसा क्यों ? गलत व सही का मूल्यांकन कौन करेगा । रेवड़ी कल्चर का यह बढ़ता परिदृश्य में राजनेता अपना अपना फायदा क्यों उठा रहे हैं।

हरिहर सिंह चौहान

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। **RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**